# घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 178- गुरूवार 30 - अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028


# बंगाल में सेकेंड फेज में 92प्रतिशत वोटिंग

## नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी-भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसा,दावा- हावड़ा में सीआरपीएफ की पिटाई से बुजुर्ग की मौत

**कोलकाता,29 अप्रैल 2026।** पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के शाम 9 बजे तक के आकड़ों के मुताबिक, 92.32% वोटिंग हुई है। यह और बढ़ सकता है। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा, झड़प, लाठीचार्ज और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आईं। नॉर्थ 24 परगना के अरविंद रैली में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर मुक्के, लाठियों से हमले किए। भारी संख्या में सुरक्षाबलों की मौजूदगी के बावजूद हालात बेकाबू दिखे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के हमले से हावड़ा के उदयनारायणपुर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने गए थे। केंद्रीय बलों ने उन्हें धक्का दिया और मारपीट की। बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

### ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया

भाजपा ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फालता में ईवीएम में बीजेपी का बटन टेप लगाकर ब्लॉक किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां भी शिकायतें सही मिलीं, वहां दोबारा चुनाव होंगे। पानीहाटी में ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर इंक का दाग होने की शिकायत सामने आई। उसे सैनिटाइजर से साफ किया गया।

### हावड़ा में वोट डालने आए बुजुर्ग की मौत

हावड़ा के उदयनारायणपुर में वोट डालने आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने गए थे। केंद्रीय बलों ने उन्हें धक्का दिया और मारपीट की। बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

### सुवेंदु के खिलाफ 'गो बैक' और 'चोर-चोर' के नारे

भवानीपुर में ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी को घेरकर टीएमसी समर्थकों ने चोर-चोर के नारे लगाए। सुवेंदु एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे। सुवेंदु जब कालीघाट में ममता के आवास से करीब 100 मीटर दूर सड़क से गुजर रहे थे, तब लोगों ने 'गो बैक' के नारे लगाए। सुवेंदु ने भी जवाब में जय श्री राम के नारे लगाए।

### हावड़ा में वोटरों पर लाठीचार्ज

हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र के लिलुआ में बूथ नंबर 151, 152 और 153 पर केंद्रीय बलों ने वोटरों पर लाठीचार्ज किया। आरोप है कि ईवीएम मशीनों में खराबी के कारण वोटर लंबे समय तक लाइन में खड़े थे। बाद में उन्होंने हंगामा किया तो उनपर लाठीचार्ज हुआ।

### सुरक्षाबलों और वोटरों के बीच धक्का-मुक्की

साउथ 24 परगना के कैनिंग में टीएमसी उम्मीदवार परेश राम दास ने आरोप लगाया कि एक बूथ पर पोलिंग एजेंट को सीआरपीएफ कर्मियों ने पीटा और बूथ से बाहर घसीट दिया। बूथ से आई तस्वीरों में महिलाएं सहित कई लोग सुरक्षाबलों से धक्का-मुक्की करते दिखे।

# बंगाल : 8 एग्जिट पोल में से 6 में भाजपा सरकार

## असम में बीजेपी,तमिलनाडु में डीएमके की वापसी केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार का अनुमान

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल आ गए हैं। सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में है, जहां आठ में से छह पोल भाजपा की ऐतिहासिक जीत और सत्ता परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। वहीं, असम और पुदुचेरी में भाजपा-एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखता दिख रहा है। दक्षिण की बात करें तो केरल में यूडीएफ की शानदार वापसी हो रही है, जबकि तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन आगे है। मैट्रिज के सर्वे के अनुसार, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 146 से 161 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में भाजपा इस जादुई आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। पार्टी के पक्ष में 42.5% वोट शेयर जाने का अनुमान जताया गया है। यह आंकड़ा भाजपा के लिए अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन साबित हो सकता है।

## प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्व की पहली 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' का किया अवलोकन

**वाराणसी/भोपाल,29 अप्रैल 2026।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ को समर्पित विश्व की पहली 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' का अवलोकन किया। यह घड़ी भारतीय वैदिक कालगणना पर आधारित है और आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राचीन समय गणना पद्धति को जीवंत रूप देती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, 3 अप्रैल 2026 को यह विशेष घड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की थी। इसके अगले दिन 4 अप्रैल 2026 को इसे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार डॉ. श्रीराम तिवारी ने बताया कि कालगणना की नगरी उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की गई थी, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को किया था। यह घड़ी वैदिक कालगणना के सभी प्रमुख घटकों को समाहित करती है और सूर्योदय के आधार पर संचालित होती है। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर सूर्योदय का समय होता है, उसी के अनुसार वहां की कालगणना इस घड़ी में प्रदर्शित होती है। साथ ही भारतीय मानक समय (आईएसटी), वैदिक समय, लोकेशन, भारतीय पंचांग, विक्रम संवत् मास, ग्रहों की स्थिति, भद्रा, चंद्र स्थिति और अन्य ज्योतिषीय जानकारियां भी इसमें उपलब्ध रहती हैं।

## 13 मंजिला इमारत में भीषण आग...

### 8 फ्लैट जलकर खाक,जान बचाने के लिए सड़कों पर भागे लोग,करोड़ों का नुकसान

**गाजियाबाद,29 अप्रैल 2026।** यूपी के गाजियाबाद में बुधवार की सुबह चीख-पुकार मच गई। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी की 13 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मैदानी सूत्रों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि 9वीं से लेकर 12वीं मंजिल तक के 8 फ्लैट पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर जूझ रही हैं। बता दें कि इस हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान 12वें फ्लोर पर रहने वाले सुनील के परिवार को हुआ है। सुनील उस वक्त दिल्ली में थे। उन्होंने बताया कि जब फोन आया तो घर में बच्चे रो रहे थे और चारों तरफ धुआं था। उनका ढाई करोड़ का फ्लैट उनकी आंखों के सामने जल गया। सुनील का गंभीर आरोप है कि सोसाइटी में आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे, बिल्डर ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लपटें एक टावर से दूसरे टावर तक छलांग मार गईं। दरअसल, हवा की वजह से आग ने पास के दो और फ्लैटों को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि आग लगते ही लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और समय रहते पूरी इमारत खाली कर दी गई। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस बल तैनात है। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति जल गई है।

## मानसा कोर्ट का आदेश...खुद पेश हों मुख्यमंत्री भगवंत मान, नहीं तो 'जमानत होगी रद्द

**चंडीगढ़,29 अप्रैल 2026।** पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मानसा की एक स्थानीय कोर्ट ने सीएम भगवंत को एक मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक नजर सिंह मानशाहिया द्वारा सीएम भगवंत सिंह मान के खिलाफ दायर मामले में यह सुनवाई हुई। आरोपी ने चंडीगढ़ में एक जरुरी बैठक का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी। मानसा के पूर्व विधायक नजर सिंह मानशाहिया ने मुख्यमंत्री पर आरोप लागया था कि, जुलाई 2019 में पार्टी छोड़ने के बाद संगरूर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मान ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं,जिसके बाद उन्होंने अदालत का रूख किया। जानकारी के मुताबिक,पिछली सुनवाई में मुख्यमंत्री की वर्चुअली मौजूदगी को अदालत ने खारिज कर दी थी और 28 अप्रैल को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। लेकिन सीएम मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हो सके।

## प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया...

# बंगाल जैसी बंपर वोटिंग दशकों में नहीं देखी : पीएम मोदी

**हरदोई,29 अप्रैल 2026।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूपी के हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने ऐलान किया कि एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। पीएम ने सपा और कांग्रेस पर कहा...सपा विकास और नारी विरोधी है। बीते दिनों एक बार फिर देश ने इनका नारी विरोधी चेहरा देखा है। इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन के खिलाफ वोट किया। पीएम ने पश्चिम बंगाल में चल रही दूसरे चरण की वोटिंग का जिक्र किया। कहा...जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। ऐसी वोटिंग दशकों में नहीं देखी। इससे पहले पीएम ने एक्सप्रेस-वे के किनारे पेड़ लगाया। सीएम योगी के साथ एक्सप्रेस-वे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। अब तक 11-12 घंटे लगते थे। एक्सप्रेस-वे करीब 37,350 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस हिसाब से 1 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे की औसत लागत करीब 62 करोड़ 87 लाख रुपए है। मोदी ने ही 18 दिसंबर, 2021 को शाहजहांपुर में एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया था। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे था, जिसकी लंबाई 340 किमी है।

### यूपी का विकास भारत की सामरिक ताकत बन रहा

पीएम मोदी ने कहा ...अब उन कठिनाइयों का समाधान होगा। बड़े बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। यह एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। इसके किनारे औद्योगिक अवसर मिलेंगे। सभी 12 जिलों में नए उद्योग आएंगे और फार्मा के क्लस्टर विकसित होंगे। युवा नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। पुरानी सरकारों में क्या हरदोई-उन्नाव जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना हो सकती थी? क्या कोई सोच सकता था कि हरदोई से भी एक्सप्रेस-वे गुजरेगा? यह सब भाजपा सरकार में ही संभव हुआ है। यूपी को पहले पिछड़ा और बीमारू कहा जाता था, वही यूपी आज एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है।

### यह सिर्फ हाई-स्पीड सड़क नहीं है,बल्कि नए सपनों का गेटवे

**पीएम ने कहा- कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने का अवसर मिला था। यह विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं। ये आधुनिक हस्तरेखाएं हैं। वह दौर चला गया, जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो जाने के बाद सालों तक फाइलें चलती थीं। चुनाव के लिए पत्थर लगा दिया जाता था, लेकिन काम का कोई पता नहीं चलता था। फाइलें ढूंढने में अफसरों को दो-दो साल तक का समय लग जाता था।**

### मोदी ने काशी विश्वनाथ में पूजा की,त्रिशूल लहराया

काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा-अर्चना की। पांच पंडितों ने उन्हें पूजा कराई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। पीएम मंदिर से बाहर निकले तो भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। पीएम 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। मंदिर में पीएम बच्चों से भी मिले और उनसे बातचीत की। इससे पहले, पीएम के रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों पर डांस करते नजर आए। प्रधानमंत्री का जगह-जगह स्वागत किया गया। काफिले पर फूल बरसाए गए। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि, वह कहीं रुके नहीं। काशी से पीएम हरदोई के लिए रवाना हो गए हैं। वहां गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री का 11 साल में यह 54वां काशी दौरा है। हालांकि, यह 2026 का पहला दौरा है। इससे पहले, पीएम नवंबर 2025 में काशी आए थे।

## बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर...

### अस्पताल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत,तीन बच्चे भी शामिल

**बेंगलुरु,29 अप्रैल 2026।** कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बुधवार शाम को हुई भारी बारिश के कारण 7 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। खबर के मुताबिक, शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। यहां बारिश के कारण बॉरिंग और लेडी कर्जन हॉस्पिटल की दीवार गिरने का शक है। आशंका है कि तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, मरने वालों में कुछ स्ट्रीट वेंडर थे जो अस्पताल के पास फुटपाथ पर ठेला चलाते थे। माना जा रहा है कि दीवार गिरने के कारण कुछ राहगीर भी फंस गए हैं। चश्मदीदों ने बताया कि, भारी बारिश के कारण वेंडर और पैदल चलने वाले लोग एक पुरानी दीवार के पास छिप गए थे। बारिश तेज होने पर उन्होंने एक बड़ी तिरपाल शीट का इस्तेमाल कर बारिश से बचने की कोशिश की। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, जैसे ही बारिश और हवाएं अचानक तेज हुईं, लोग तिरपाल के नीचे इकट्ठा हो गए और कुछ ही पलों में दीवार गिर गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया।

## सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते,हम इस देश की सभ्यता और धार्मिक इतिहास नहीं भूल सकते : सुप्रीम कोर्ट

**नई दिल्ली,29 अप्रैल 2026।** केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की दलीलों के जवाब में कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जयसिंह ने सुनवाई के 10वें दिन कहा कि सबरीमाला मंदिर में एंट्री का फैसला अब भी लागू है। इस पर स्टे नहीं है लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। जयसिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई कर रहा है। हालांकि,कोर्ट कभी यह तय नहीं करता कि धर्म में क्या जरूरी है या और क्या नहीं। इसका फैसला तो धर्म ही करता है। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हम इस भूमि के सभ्यता के विकास और धार्मिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी बैकग्राउंड से संविधान के आर्टिकल 25 और 26 आए हैं। संविधान और बाकी सब ठीक है लेकिन हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। आप अतीत को नजरअंदाज करके यह नहीं कह सकते कि यह एक कोरी स्लेट है। इस पर जयसिंह ने कहा कि इस पर डिबेट हो सकती है। यह क्लीन स्लेट है। सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखीं। सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है,इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

**कोर्ट बोला...हम धार्मिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं :** जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हम इस भूमि के सभ्यता के विकास और धार्मिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आखिर इसी बैकग्राउंड से संविधान के आर्टिकल 25 और 26 आए हैं। संविधान और बाकी सब ठीक है लेकिन हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। इतिहास ही वर्तमान का निर्माण करता है। आप अतीत को नजरअंदाज करके यह नहीं कह सकते कि यह एक कोरी स्लेट है। इस पर जयसिंह ने कहा कि इस पर डिबेट हो सकती है। यह क्लीन स्लेट है।

**क्या हम इस मुद्दे पर लुका-छिपी क्यों खेल रहे हैं?** इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अनुच्छेद 25(2) को अनुच्छेद 26(बी) से ऊपर मानने के सुझाव सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। हालांकि, ऐसे तर्क के पीछे के कारण नहीं बताए गए। साथ ही, यदि हम इस बात से सहमत हैं कि अनुच्छेद 25(2), अनुच्छेद 25(1) को नियंत्रित करता है तो एक महिला होने के नाते मुझे मंदिर में प्रवेश करने से क्या रोकता है? हम इस मुद्दे के दायरे को लेकर लुका-छिपी क्यों खेल रहे हैं?

## गुजरात के साबरकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा

### बस ने एक वैन को मारी टक्कर,8 की मौत

**साबरकांठा,29 अप्रैल 2026।** गुजरात के साबरकांठा जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने हाईवे पर एक वैन को पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना तब घटी जब वैन शमलाजी से हिम्मतनगर की तरफ जा रही थी। दुर्घटना के समय वैन सड़क पर चल रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने उसे जोरदार टक्कर मारी। पुलिस का कहना है कि बस की गति बहुत ज्यादा थी, जो इस हादसे का मुख्य कारण बनी। टक्कर इतनी तीव्र थी कि वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, और उसमें सवार लोग बुरी तरह से फंस गए।

**मृतकों और घायलों की स्थिति :** इस दुर्घटना में वैन में सवार छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। चार अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा काफी भयंकर था, और स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर घायलों को वैन से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। दुर्घटना के बाद, पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। गंभोई पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अल्पेश चौधरी ने बताया कि यह हादसा मुख्य रूप से बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ है।

## मध्य प्रदेश के धार में पिकअप वाहन पलटा,12 की मौत

**धार,29 अप्रैल 2026।** मध्य प्रदेश के धार में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन स्कॉर्पियो को टक्कर मारने के बाद पलट गया। हादसे में अब तक दो बच्चों समेत 12 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। 13 गंभीर रूप से घायल हैं। एक्सीडेंट इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चिकलिया फाटा पर जिओ पेट्रोल पंप के पास बुधवार रात करीब साढ़े 8 बजे हुआ। धार जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि 10 लोगों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मृतकों के परिजन पोस्टमॉर्टम रूम के बाहर शवों की पहचान करने में जुटे हैं।

## आसाराम को हाईकोर्ट से मिली राहत अंतरिम जमानत 25 मई तक बढ़ी

**जोधपुर,29 अप्रैल 2026।** यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेडिकल आधार पर आसाराम की अंतरिम जमानत 25 मई तक अथवा अपील पर अंतिम निर्णय आने तक बढ़ाने का आदेश दिया। आसाराम ने बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और लंबे समय से चल रहे उपचार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने की मांग की थी। यह याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश की गई। आसाराम के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में कहा कि आसाराम वर्ष 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं और 2018 में दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद गत वर्ष भी तीन बार अंतरिम जमानत बढ़ाई जा चुकी है। वर्तमान में आसाराम 29 अक्टूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर रहकर इलाज करवा रहे हैं। वकीलों ने तर्क दिया कि यदि जमानत अवधि आगे नहीं बढ़ाई तो उपचार अधूरा रह जाएगा।

## संपादकीय

# ममता के सामने गढ़ बचाने की चुनौती

इस महीने की नौ तारीख से चार राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों का आरंभ हुआ सिलसिला अब अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान के बाद सभी निगाहें चार मई को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी रहेंगी। बंगाल चुनाव के पहले चरण में हुए रिकार्ड 92 प्रतिशत मतदान के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। जहां तृणमूल इस बंपर मतदान को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में भरोसे के साथ जोड़कर प्रस्तुत कर रही है, वहीं भाजपा इसे सत्ता विरोधी रुझान के रूप में प्रचारित करने में लगी है। पहले चरण की 152 सीटें मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल और जंगल महल के इलाकों में केंद्रित थीं तो दूसरे चरण का मतदान उस दक्षिण बंगाल में होना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सत्ता की कुंजी इसी क्षेत्र के हाथ में होती है।

बंगाल के राजनीतिक गलियारों में यह कहावत आम है कि जिसने प्रेसिडेंसी वाले इलाकों में जीत हासिल की,वही नबन्ना (पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय) पर काबिज हुआ। यह विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बहुत निर्णायक है,क्योंकि हार की स्थिति उन्हें हाशिए पर पहुंचा सकती है। तृणमूल मुख्य रूप से बंगाल केंद्रित पार्टी है और आस-पड़ोस के राज्यों से लेकर गोवा तक राजनीतिक विस्तार के उसके प्रयास फलीभूत नहीं हो पाए हैं। इस स्थिति में अगर बंगाल उसके हाथ से निकलता है तो फिर राजनीतिक पूंजी पूरी तरह सिमट जाएगी। जबकि जीत की स्थिति न केवल बंगाल, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी के कद को बहुत ऊंचे स्तर पर स्थापित करने का काम करेगी।

ज्योति बसु और नवीन पटनायक के बाद वह किसी बड़े राज्य की पहली मुख्यमंत्री बन जाएंगी, जो लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करने में सफल होंगी। बंगाल का राजनीतिक मिजाज देखें तो यह राज्य लंबे समय तक ही एक ही ढर्रे पर चलता आया है। वर्ष 1977 से 2026 के बीच यहां केवल एक बार ही सत्ता परिवर्तन हुआ,जब 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने तीन दशकों से अधिक पुरानी वामपंथी सत्ता को अपदस्थ किया था। उसके बाद से ममता और तृणमूल का सिक्का ही सत्ता पर जमा हुआ है।

पहले चरण की जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ है,उनमें प्रतिद्वंद्वी भाजपा की ताकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो 77 सीटें मिली थीं, उनमें से 59 सीटें इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों की थीं। जबकि दूसरे चरण की जिन 142 सीटों पर चुनाव होना है,उनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल को 123 सीटें मिली थीं और भाजपा को मात्र 18 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा था। स्पष्ट है कि अगर भाजपा को राज्य की सत्ता पर अपना दावा मजबूत करना है तो कोलकाता, हावड़ा,हुगली,नदिया और 24 परगना क्षेत्रों में भी जीत हासिल करनी होगी। इसके बिना तृणमूल कांग्रेस के समक्ष चुनौती पैदा करना आसान नहीं होगा।

पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल को जहां 48 प्रतिशत वोट मिले, वहीं भाजपा की झोली में 38 प्रतिशत मत आए थे। इस बड़े अंतर का ही परिणाम रहा कि तृणमूल को 215 सीटों के साथ अपने इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल हुई। अब देखना यह होगा कि क्या तृणमूल अपनी यह बढ़त कायम करने में सफल रहती है या भाजपा उसकी सियासी जमीन में सेंध लगा पाती है? इस सवाल का जवाब कई परतों में छिपा है।

बंगाल उन राज्यों में से एक है,जहां की जनसांख्यिकी भाजपा की राजनीति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। राज्य में मुस्लिम समुदाय की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के चलते कई सीटों पर उसकी भूमिक निर्णायक बन जाती है।

# स्कूल की चौखट पर खड़ा बाजार,और भीतर सिमटती शिक्षा

**शिक्षा के गलियारों में बाज़ार की आहट,पाठ्यपुस्तक बना माध्यम**
**नियमों की मौजूदगी में भी अव्यवस्था,शिक्षा प्रणाली पर प्रश्नचिह्न**

प्रो.आर.के.जैन 'अरिजीत'
बड़वानी,मध्यप्रदेश

निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी पुस्तकों के अनुपालन का सवाल अब महज़ पाठ्य सामग्री का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह देश की शिक्षा व्यवस्था के चरित्र की परीक्षा बन चुका है। जब एक ओर कानून स्पष्ट दिशा देता हो और दूसरी ओर संस्थान स्वार्थवश उससे भटकें,तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि नैतिक विचलन का संकेत होता है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केंद्र,सी बी एस ई और सभी राज्यों को जारी नोटिस ने इस विडंबना को उजागर किया है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा का अधिकार कानून केवल औपचारिक घोषणा बनकर रह गया है, या उसे लागू करने की प्रतिबद्धता ही क्षीण हो गई है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि शिक्षा में समानता का मूल सिद्धांत निरंतर दबाव और उपेक्षा के बीच संघर्ष कर रहा है।

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की धारा 29 ने स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण एनसीईआरटी या संबंधित एससीईआरटी द्वारा किया जाएगा। इसी सोच के तहत एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण का अधिकार सौंपा गया। इन संस्थाओं द्वारा तैयार पुस्तकें न केवल शैक्षणिक रूप से संतुलित और विश्वसनीय होती हैं, बल्कि आम परिवारों के लिए किफायती भी रहती हैं। इसके विपरीत,निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें इस मूल उद्देश्य को कमजोर करती हैं। जब एक ही कक्षा की पुस्तकों पर हजारों रुपये खर्च होने लगें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा अब अधिकार से ज्यादा एक लाभकारी व्यापार में बदलती जा रही है।

निजी विद्यालयों में महंगी पुस्तकों को अनिवार्य बनाना कोई आकस्मिक भूल नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित आर्थिक तंत्र की ओर संकेत करता है। कई स्थानों पर स्कूल और प्रकाशक मिलकर ऐसा गठजोड़ रचते हैं, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य पीछे छूट जाता है और मुनाफा केंद्र में आ जाता है। अभिभावकों को उच्च गुणवत्ता और अधिक उपयोगी सामग्री का हवाला देकर इन पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि इन दावों की ठोस पुष्टि प्रायः नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों की विवशता का व्यवस्थित दोहन होता है और वे विरोध करने में असहाय महसूस करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति शिक्षा के नैतिक आधार को कमजोर करती है और संस्थागत विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

सबसे चिंताजनक परिणाम एक तेजी से गहराते शिक्षा-विभाजन के रूप में सामने आता है। जहां सरकारी विद्यालयों के बच्चे सस्ती,मानकीकृत और समान पुस्तकों से पढ़ते हैं,वहीं निजी स्कूलों के छात्र महंगी और अलग सामग्री पर निर्भर होते हैं, जिससे उनके ज्ञान का आधार ही भिन्न बन जाता है। यही अंतर आगे चलकर अवसरों की खाई को और चौड़ा कर देता है। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार पहले से ही शिक्षा पर बढ़ते खर्चों का दबाव झेल रहे हैं, ऐसे में किताबों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उनके लिए बेहद असहनीय हो जाता है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को नहीं बढ़ाती, बल्कि समाज में गहराते असंतुलन और विभाजन को भी और मजबूत करती है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल एक महत्वपूर्ण और समयोचित हस्तक्षेप के रूप में सामने आती है,जिसने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता को और स्पष्ट किया है। अनावश्यक तथा भारी-भरकम पुस्तकों का बढ़ता बोझ बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो राष्ट्रीय स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की मूल भावना के विपरीत है। यदि राज्य सरकारें और संबंधित संस्थाएं अब भी इस मुद्दे पर उदासीन बनी रहती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक अक्षमता नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्वों की स्पष्ट उपेक्षा मानी जाएगी। इसलिए इस विषय को अब सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ठोस और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

अकादमिक स्वायत्तता का तर्क अक्सर इस व्यवस्था को सही ठहराने के लिए दिया जाता है,पर इसकी वैधता तभी तक है जब तक वह कानून की सीमाओं में रहे। जब विधि स्पष्ट रूप से तय करती है कि पाठ्यपुस्तकों का चयन किन संस्थाओं के अधिकार में होगा, तब उस सीमा का उल्लंघन स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अनुशासनहीनता का संकेत है। एनसीईआरटी की पुस्तकें विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार होती हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता सिद्ध होती है। इसके विपरीत, निजी प्रकाशनों में आकर्षण अधिक,पर सामग्री की प्रमाणिकता पर सवाल बने रहते हैं। ऐसे में अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देना शिक्षा की मूल भावना के विरुद्ध है।

अब समय महज़ चर्चा का नहीं, ठोस और निर्णायक हस्तक्षेप का है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक पारदर्शी, कड़ा और जवाबदेह निगरानी तंत्र विकसित करना होगा,जो कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर प्रभावी दिखे। निजी विद्यालयों की पुस्तक सूचियों का नियमित, निष्पक्ष और व्यापक ऑडिट सुनिश्चित किया जाए, तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई हो। जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द करने तक के प्रावधानों को पूरी दृढ़ता के साथ लागू करना अनिवार्य है। साथ ही अभिभावकों को जागरूक और सशक्त बनाना होगा, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी अनावश्यक आर्थिक बोझ के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठा सकें।

आखिरकार यह प्रश्न केवल किताबों तक सीमित नहीं,बल्कि राष्ट्र के भविष्य और उसकी सामाजिक दिशा से गहराई से जुड़ा है। शिक्षा वही मजबूत आधार है जिस पर एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की इमारत खड़ी होती है, और यदि इसी आधार में असमानता की दरार पड़ जाए,तो समावेशी विकास का सपना अधूरा रह जाता है। समान पाठ्य सामग्री सिर्फ शैक्षणिक जरूरत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का एक अहम स्तंभ है। अब सरकार और समाज–दोनों के सामने यह स्पष्ट विकल्प है कि शिक्षा को बराबरी का सेतु बनाया जाए या उसे विभाजन की खाई में बदलने दिया जाए।

# उच्च शिक्षा में 'मार्केट फॉर लेमन्स'

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार, हरियाणा

भारत में उच्च शिक्षा का तीव्र विस्तार अवसरों के साथ-साथ गंभीर चुनौतियाँ भी लेकर आया है। एक ओर विश्वविद्यालयों,महाविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे समय में अर्थशास्त्री जॉर्ज अकेलॉफ का 'मार्केट फॉर लेमन्स' सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक दिखाई देता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब उपभोक्ता को किसी वस्तु की वास्तविक गुणवत्ता की सही जानकारी नहीं होती,तब निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार पर हावी हो जाते हैं और अच्छे उत्पाद पीछे हट जाते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी उपभोक्ता हैं और संस्थान सेवा प्रदाता। जब विद्यार्थियों को संस्थानों की वास्तविक स्थिति, शिक्षकों की गुणवत्ता, रोजगार संभावनाओं,शोध कार्य और आधारभूत सुविधाओं की सही जानकारी नहीं मिलती, तब वे कमज़ोर संस्थानों में प्रवेश लेने को विवश हो जाते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार मुख्य रूप से नीतिगत प्रयासों के कारण हुआ है। नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने,दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने,ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षित करने पर बल दिया। इससे शिक्षा तक पहुँच बढ़ी और अधिक विद्यार्थियों को अवसर मिला,परंतु संस्थानों की गुणवत्ता उसी गति से विकसित नहीं हो सकी। अनेक निजी संस्थान आकर्षक विज्ञापन,भव्य परिसर और बड़े-बड़े दावे करके विद्यार्थियों को अपनी ओर खींचते हैं,जबकि वास्त विकता में वहाँ योग्य शिक्षक,शोध वातावरण और रोजगारपरक शिक्षा का अभाव होता है। सरकारी आँकड़े भी अक्सर विलंब से आते हैं या सामान्य लोगों की समझ से परे जटिल रूप में उपलब्ध होते हैं। परिणामस्वरूप विद्यार्थी और अभिभावक सही निर्णय नहीं ले पाते। यही स्थिति निम्न गुणवत्ता वाले शिक्षा बाजार को जन्म देती है।

इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ की। इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन निश्चित मानकों के आधार पर करना है। इसमें शिक्षण व्यवस्था,संसाधन, शोध कार्य,स्नातक परिणाम,समावेशन और प्रतिष्ठा जैसे पहलुओं को देखा जाता है। इस व्यवस्था ने पहली बार विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच दिया जहाँ वे विभिन्न संस्थानों की तुलनात्मक स्थिति जान सकते हैं। इससे संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अनेक महाविद्यालयों तथा विश्व विद्यालयों ने शिक्षकों की नियुक्ति,शोध प्रकाशनों, रोजगार सहायता केंद्रों और आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना प्रारंभ किया।

इस रैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता के संकेत उपलब्ध कराए। अब विद्यार्थी केवल विज्ञापनों या प्रचार सामग्री पर निर्भर नहीं रहते,बल्कि संस्थान की स्थिति,शोध प्रदर्शन, परीक्षा परिणाम और समावेशन जैसी जानकारियों को देखकर निर्णय ले सकते हैं। इससे सूचना के अभाव की समस्या में कुछ कमी आई है। सरकार के लिए भी यह एक महत्त्वपूर्ण नीति उपकरण सिद्ध हुआ है,जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थानों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन संभव हुआ है।

फिर भी यह व्यवस्था पूर्ण समाधान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह काफी हद तक संस्थानों द्वारा स्वयं दिए गए आँकड़ों पर आधारित रहती है। यदि कोई संस्थान गलत या बढ़ा-चढ़ाकर जानकारी दे, तो रैंकिंग की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। दूसरा, शोध कार्य को अधिक महत्व मिलने से वे महाविद्यालय पीछे रह जाते हैं जो मुख्य रूप से शिक्षण पर केंद्रित हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों या नवस्थापित संस्थानों के लिए बड़े और पुराने शहरी संस्थानों से प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। चौथा, रैंकिंग वर्ष में एक बार आती है,जबकि विद्यार्थियों को कई बार वास्तविक समय की जानकारी की आवश्यकता होती है। पाँचवाँ,देश के विशाल उच्च शिक्षा ढाँचे की तुलना में सीमित संस्थान ही प्रमुखता से सामने आते हैं, जिससे अनेक संस्थान पारदर्शी मूल्यांकन से बाहर रह जाते हैं।

विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के लिए ऐसे मॉडल अपनाए जाते हैं जिनमें पूर्व छात्रों की संतुष्टि, अंतरराष्ट्रीय पहचान, नियोक्ताओं की राय,शोध प्रभाव और वैश्विक सहयोग जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया जाता है। भारत भी अपनी व्यवस्था को अधिक व्यापक और बहुआयामी बनाकर इन अनुभवों से सीख सकता है।

विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ ठोस सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, संस्थानों द्वारा दिए गए आँकड़ों का स्वतंत्र एजेंसियों से सत्यापन कराया जाए,ताकि गलत जानकारी देने की प्रवृत्ति समाप्त हो। दूसरा, शिक्षण गुणवत्ता, छात्र-शिक्षक अनुपात, रोजगार उपलब्धता और शुल्क के मुकाबले लाभ को अधिक महत्व दिया जाए। तीसरा, केवल क्रम संख्या देने के स्थान पर समूह आधारित श्रेणी व्यवस्था अपनाई जाए,जिससे छोटे और उभरते संस्थानों को भी सम्मानजनक स्थान मिल सके। चौथा,एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच विकसित किया जाए जहाँ प्रत्येक संस्थान की अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो। पाँचवाँ,राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर भी रैंकिंग तैयार की जाए,ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को अपने आसपास बेहतर विकल्प मिल सकें। छठा,विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया को भी मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए।

अंततः उच्च शिक्षा केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि गुणवत्ता,विश्वास और समान अवसर का प्रश्न है। यदि पारदर्शिता का अभाव रहेगा तो विद्यार्थी निम्न स्तर के संस्थानों के जाल में फँसते रहेंगे और उनका भविष्य प्रभावित होगा। राष्ट्रीय रैंकिंग व्यवस्था ने सकारात्मक शुरुआत अवश्य की है,किंतु इसे अधिक स्वतंत्र, विश्वसनीय और विद्यार्थी-केंद्रित बनाना समय की आवश्यकता है। जब सही जानकारी,प्रभावी नियमन और गुणवत्ता पूर्ण संस्थान एक साथ सामने आएँगे,तभी भारत वास्तव में ज्ञान आधारित विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकेगा।

# ईमानदारी के संकल्प से गूँजता एक विशेष दिवस

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्य प्रदेश

ईमानदारी दिवस हमारे नैतिक चरित्र को सशक्त बनाने और समाज में सच्चाई के प्रति विश्वास जगाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसे हमें केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में अपनाना चाहिए। आज के दौर में जब हर तरफ प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का बोलबाला है तब ईमानदारी ही वह एकमात्र तत्व है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करता है और उसे समाज में विशिष्ट पहचान दिलाता है। वास्तव में ईमानदारी का अर्थ केवल आर्थिक लेन-देन में स्पष्टता रखना या पुलिस और कानून के डर से अपराध न करना ही नहीं है बल्कि इसका वास्तविक अर्थ अपने विचारों और अपनी अंतरात्मा के प्रति पूर्ण रूप से पारदर्शी होना है।जब एक व्यक्ति ईमानदारी का मार्ग चुनता है तो उसे मानसिक शांति और असीम आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है क्योंकि उसे किसी भी झूठ को छुपाने के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। पेशेवर जगत में भी सच्चाई और निष्ठा ही वह नींव है जिस पर बड़े-बड़े संस्थानों और व्यापारिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी समझौता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हमारे सामाजिक ढांचे में भी ईमानदारी का उतना ही महत्व है जितना कि शरीर में प्राणों का क्योंकि यदि नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो राष्ट्र की प्रगति की कल्पना करना भी व्यर्थ है।

आजकल की दिखावे वाली संस्कृति में अक्सर लोगों को लगता है कि चालाकी और झूठ से वे जल्दी सफ़लता प्राप्त कर लेंगे परंतु ऐसी सफलता रेत के महल की तरह होती है जो समय की एक छोटी सी लहर से ढह जाती है। इसके विपरीत ईमानदारी से हासिल की गई उपलब्धि भले ही देर से मिले लेकिन वह अत्यंत ठोस और सम्मानजनक होती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनती है। राष्ट्रीय ईमानदारी दिवस पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के हर छोटे-बड़े निर्णय में सच्चाई का साथ देंगे और एक ऐसे पारदर्शी वातावरण का निर्माण करेंगे जहां छल-कपट का कोई स्थान न हो। अंततः हमें यह समझना होगा कि ईमानदारी किसी दूसरे पर किया गया उपकार नहीं है बल्कि यह स्वयं के चरित्र को संवारने और एक सुखी जीवन जीने का सबसे सरल मार्ग है।

# शीशे के पार एक अधूरी चीख

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

उस अठारह गुणा चौबीस के कांच के टुकड़े पर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। ड्रेसिंग टेबल के उस पार खड़ी माया अपनी उंगलियों से उस सतह को सहला रही थी, हाँ सूखे गोंद के निशानों ने एक अजीब सा नक्शा बना दिया था। वहां लाल, नीली और सुनहरी बिंदियों का एक जमघट था। कुछ के रंग उड़ चुके थे,कुछ का मखमल घिस गया था, और कुछ बस अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कांच से लटकी थीं। तुम इन्हें हटाती क्यों नहीं? मैंने गलियारे से गुजरते हुए पूछा। माया ने बिना मुड़े जवाब दिया, इतिहास मिटाया जाता है, विसर्जित नहीं किया जाता। उसकी आवाज में वह भारीपन था जो अक्सर पुराने मकानों की सीलन में होता है। वह आईना नहीं था, वह उन लम्हों की एक ऐसी नुमाइश थी जहाँ हर बिंदी एक मुकम्मल दास्तान दबाए बैठी थी। शहर के इस शोरगुल वाले फ्लैट में वह कोना एक ऐसी शांत घाटी बन गया था, जहाँ समय रुकने का ढोंग कर रहा था। जैसे-जैसे दिन ढलते गए, उस कांच पर बिंदियों की तादाद बढ़ती ही गई। ऐसा लगता था कि माया अपनी माथे की रौनक को हर रात उस ठंडे कांच पर गिरवी रख देती है। आज फिर एक नई? मैंने छेड़ा। उसने शीशे में मुझे देखते हुए कहा, सिर्फ एक और गवाह। वह आईना अब एक चेहरा नहीं, बल्कि एक रोजनामचा बन चुका था। हर बिंदी एक हार थी, एक समझौता था, या शायद किसी अनकही चीख का मौन स्मारक। धूल की एक परत ने उन पर अपनी चादर बिछा दी थी, जिससे वे किसी प्राचीन शिलालेख की तरह दिखने लगी थीं। मोहल्ले की औरतें कहती थीं कि माया का श्रृंगार उसकी ताकत है, पर मुझे उस आईने को देखकर लगता था कि वह कांच हर रोज उसकी रूह का एक कतरा नोच लेता है और बदले में एक बेजान बिंदी चिपका देता है।

एक रात बारिश की झड़ी लगी थी। कमरे में बिजली गुल थी और मोमबत्ती की लौ में वे बिंदियां दीवारों पर डरावने साये बना रही थीं। हवा की सरसराहट से भी डर लग रहा था। मैंने देखा कि माया उस आईने के सामने बैठी रो रही थी। नहीं, वह रो नहीं रही थी,वह हँस रही थी—एक ऐसी हँसी जो रूह को भीतर तक कंपा दे। क्या ढूँढ रही हो उसमें? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने उन अनगिनत बिंदियों के बीच एक खाली जगह की तरफ इशारा किया। वहां एक कमी है,वह बुदबुदाई। उसकी बातें किसी अनसुलझी पहेली की तरह लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह कांच कोई मूक दर्शक नहीं,बल्कि एक ऐसा शिकारी है जो धीरे-धीरे हमारे घर की खुशियों को अपनी मखमली गिरफ्त में ले चुका है। वातावरण में एक ऐसी बेचैनी थी कि जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला हो, पर शोर बिल्कुल गायब था।

सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस आईने को छुआ,तो मंजर वह नहीं था जिसकी कल्पना किसी ने की होगी। कमरा खाली था,खिड़की खुली थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। मैं भागकर ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा। वहां आईने पर लगी वे तमाम बिंदियां गायब थीं। वहां बस एक साफ,चमकता हुआ कांच था। पर जैसे ही मेरी नजर नीचे पड़ी,मेरी चीख गले में ही फंस गई। फर्श पर माया का शरीर बेजान पड़ा था। उसके माथे पर एक भी बिंदी नहीं थी। बल्कि, वे सारी पुरानी, फीकी और धूल भरी बिंदियां अब माया के पूरे चेहरे पर नहीं, उसकी बंद आंखों के पपोटों पर, उसके होंठों पर और उसके गले के घाव पर चिपकी हुई थीं। कांच अब पूरी तरह खाली था, क्योंकि रूह ने अपना कब्रिस्तान आईने से बदलकर देह को चुन लिया था। वह आईना अब मुझे देख रहा था। उसके ठीक बीचों-बीच मेरे अपने खून से एक बिंदी लगी थी, जो मैंने खुद रात के अंधेरे में अपने माथे से उतारकर वहां चिपकाई थी, बिना यह जाने कि मैं भी उस अंतहीन कतार का अगला हिस्सा बन चुका हूँ।

**सूचना**

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

**-सम्पादक**

CMYK

# राम मंदिर रोड अग्निकांड में बड़ा मोड़ : अब जुड़ी कड़ी धाराएँ,10 साल से उम्रकैद तक सजा का प्रावधान

## भीषण आग के बाद प्रशासन सख्त,प्रोफेसर अकील अहमद अंसारी की बेबाक ग्राउंड रिपोर्टिंग बनी निर्णायक आवाज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

राम मंदिर रोड स्थित बहुचर्चित अग्निकांड मामले में अब बड़ा मोड़ सामने आया है। शुरुआती दौर में मामूली धाराओं में दर्ज प्रकरण अब गंभीर धाराओं तक पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार मामले में अब ऐसी धाराएँ जोड़ी गई हैं, जिनमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

### 23 अप्रैल को लगी थी भीषण आग

ज्ञात हो कि 23 अप्रैल 2026 को राम मंदिर रोड स्थित मुकेश प्लास्टिक एवं पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई थी। आग इतनी भयावह थी कि दमकल विभाग को आग बुझाने में करीब 20 घंटे का समय लगा। बताया गया कि इस दौरान लगभग 5 लाख लीटर पानी खर्च हुआ। घटना के कई दिनों बाद तक मौके से धुआं निकलता रहा।

### शहर के बीच पटाखा दुकान संचालन पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया कि संबंधित दुकान का लाइसेंस शहर के बाहर का बताया जा रहा था,जबकि घनी आबादी वाले राम मंदिर रोड क्षेत्र में पटाखों और ज्वलनशील सामग्री की बिक्री खुलेआम हो रही थी। इससे प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े हुए।

### अकील अहमद अंसारी की आवाज बनी जनआंदोलन का चेहरा

इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता एवं असिस्टेंट प्रोफेसर अकील अहमद अंसारी ने विशेष भूमिका निभाई। घटना के बाद उन्होंने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए पीड़ित परिवारों,स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों की समस्याओं को खुलकर सामने रखा। अकील अहमद अंसारी ने सोशल मीडिया लाइव और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से प्रशासन से सवाल किए,जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई और मामले को दबाने की कोशिशों पर खुलकर आवाज बुलंद की। शहर में माना जा रहा है कि यदि उन्होंने लगातार यह मुद्दा नहीं उठाया होता,तो मामला कमजोर पड़ सकता था।

### जनदबाव के बाद बढ़ी कार्रवाई

26 अप्रैल की रात पुलिस ने अपराध क्रमांक 259/2026 दर्ज किया था, लेकिन शुरुआती धाराएँ हल्की बताई जा रही थीं। इसके बाद लगातार जनदबाव और अकील अहमद अंसारी जैसे जागरूक नागरिकों की सक्रियता के चलते जांच का दायरा बढ़ा। 27 अप्रैल को फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

### आईजी के हस्तक्षेप से आई तेजी

सूत्रों के अनुसार सरगुजा संभाग के आईजी दीपक कुमार झा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएँ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। साथ ही विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण की जांच भी तेज कर दी गई।

### अकील अहमद को शहर कर रहा सलाम

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अकील अहमद अंसारी ने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए सच को सामने लाने का कार्य किया। उन्होंने यह साबित किया कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनहित का मुद्दा उठाए तो प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ती है।

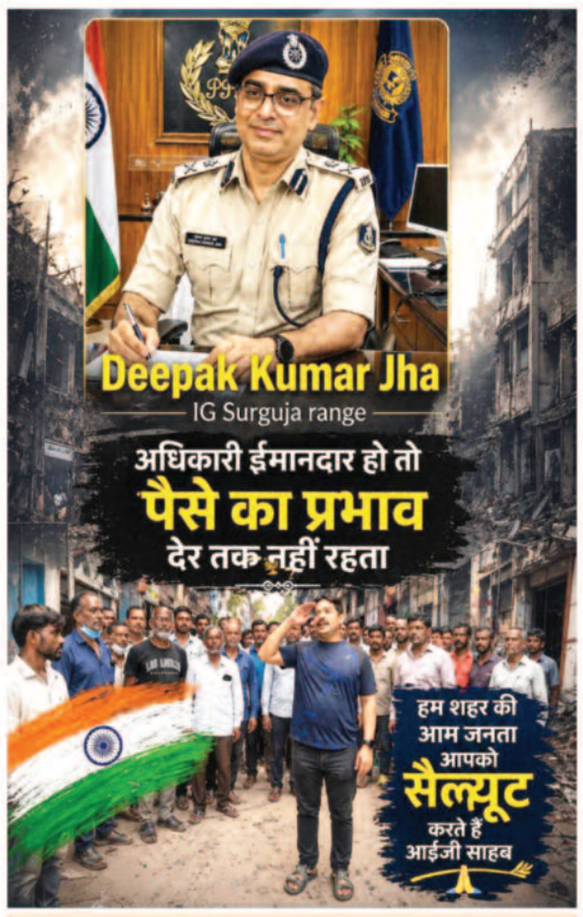


### जनता की मांग-दोषियों पर हो कड़ी सजा

अब शहरवासियों की मांग है कि इस अग्निकांड के लिए जिम्मेदार लोगों, नियमों की अनदेखी करने वालों और अवैध कारोबार को संरक्षण देने वालों पर कठोर कार्रवाई हो,ताकि भविष्य में ऐसी भयावह घटना दोबारा न हो।

# कुंवरपुर जंगल में भीषण आग,1 किमी क्षेत्र राख,वन विभाग के प्रयास नाकाफी

## हाइवे से दिख रही लपटें,महुआ बीनने की परंपरा बनी वजह...वन्यजीवों पर खतरा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत कुंवरपुर जंगल में भीषण आग लग गई है। आग पिछले दो दिनों से लगातार फैल रही है और अब तक करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है।

अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे से सटे इस जंगल में उठती आग की लपटें दूर से ही साफ दिखाई दे रही हैं। आग की वजह से इमारती पेड़ों के साथ छोटे पौधे भी जलकर खाक हो चुके हैं। मौके पर वन विभाग की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भीषण गर्मी और तेज फैलाव के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हालात यह हैं कि आग के पास पहुंचना भी जोखिम भरा हो गया है।

**महुआ बीनने के लिए लगाई जाती है आग :** क्षेत्र में हर साल गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण महुआ बीनने की पारंपरिक पद्धति बताई जाती है। ग्रामीण महुआ के फल जल्दी गिराने के लिए पेड़ों के नीचे आग लगा देते हैं,जिससे फल नीचे गिर जाते हैं और उन्हें आसानी से बीन लिया जाता है। लेकिन यही आग कई बार अनियंत्रित होकर बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा देती है। आग की चपेट में आने से छोटे जीव-जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। जंगल में फैली आग पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

**पहले भी लग चुकी है आग :** गौरतलब है कि सप्ताह भर पहले मैनपाट के जंगलों में भी भीषण आग लगी थी, जिससे बड़े क्षेत्र में नुकसान हुआ था।

# उदयपुर के झिरमिट्टी में मिली लगभग 250 वर्ष पुरानी पाण्डु लिपि

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर एवं ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के जिला समिति के अध्यक्ष श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा जिला पंचायत सीईओ एवं समिति के सदस्य सचिव श्री विनय अग्रवाल के निर्देशन में जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए 'ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' अभियान 15 मार्च से जारी है जो 15 जून तक चलेगा। कलेक्टर श्री वसंत ने लोगों से प्राचीन पांडुलिपियों को नष्ट होने से बचाने के लिए चलाए जा रहे इस सर्वेक्षण अभियान में सहयोग प्रदान करने अपील की है। उन्होंने कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़े आदि में हस्तलिखित सामग्रियों की जानकारी देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रयास है।

### उदयपुर के झिरमिट्टी में मिली लगभग 250 वर्ष पुरानी पांडुलिपि

अभियान अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण के दौरान उदयपुर विकासखण्ड के ग्राम झिरमिट्टी में लगभग 250 वर्ष पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि प्राप्त हुई, जिनका डिजिटल संरक्षण 'ज्ञानभारतम' एप के माध्यम से किया गया। मौके पर ही मोबाइल के जरिए पांडुलिपी की फोटो अपलोड कर उन्हें जिओ टैग किया गया। अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण के दौरान जिले में मिली यह पांडुलिपि ग्राम झिरमिट्टी के निवासी श्री शैलेंद्र मिश्रा के घर से प्राप्त हुई।

# 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप...2 भाग निकली

## शादी समारोह से लौटते समय 8-9 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम चारों नाबालिगों की उम्र 15 वर्ष से बताई जा रही है कम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इससे थाना क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल एक ही गांव की 4 नाबालिग लड़कियां शादी समारोह में शामिल होकर देर रात घर लौट रही थीं,इसी दौरान बाइक पर सवार 8-9 लड़कों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान 2 किसी तरह भाग निकलीं,लेकिन 2 लड़कियों के साथ अलग-अलग जगह ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया। इस घटना में सबसे दुःखद पहलू यह है कि दूसरे दिन एक नाबालिग ने थाने में जाकर घटना की जानकारी दी,लेकिन पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं किया और न ही पीड़िता का एमएलसी कराया। इसे लेकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि 24 अप्रैल की शाम एक ही गांव की 4 नाबालिग सहेलियां दूसरे मोहल्ले में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने शाम करीब 7 बजे गई थीं। वहां से चारों रात करीब 10 बजे घर लौट रही थीं। इसी दौरान हाईस्कूल के पास 5-6 बाइक पर सवार 8-10 लड़कों ने उन्हें रोक लिया। वे उनसे छेड़छाड़ करने लगे। इसी बीच एक नाबालिग किसी तरह वहां से भाग निकली, जबकि युवकों ने 3 लड़कियों को पकड़ रखा। इसके बाद 4 युवक एक नाबालिग को हाईस्कूल से दूर खेत में ले गए। यहां चारों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जबकि दूसरी नाबालिग के साथ हाईस्कूल के पास ही 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। तीसरी बाइक से कूदकर भागी आरोपी तीसरी नाबालिग को बाइक पर बैठाकर दूर ले जा रहे थे। इस दौरान उसने बाइक पर पीछे बैठने की जिद की। इस पर युवकों ने उसे पीछे बैठा लिया। इसी बीच रास्ते में वह बाइक से कूदकर भागने लगी। युवकों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया,लेकिन वह खेतों के रास्ते भागने में कामयाब रही। दूसरे दिन एक नाबालिग पहुंची थाना रात करीब 2 बजे गैंगरेप पीड़िता 2 नाबालिग अपने घर पहुंची,लेकिन डर से रात में उन्होंने परिजनों को कुछ नहीं बताया। 25 अप्रैल की शाम एक नाबालिग ने परिजन को ये बात बताई। इसके बाद वे संबंधित थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। लेकिन यहां पुलिस ने न तो तत्काल एफआईआर लिखी और न ही बालिका का एमएलसी कराना उचित समझा। उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा गया।

**26 अप्रैल को लिखी एक की रिपोर्ट :** बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को पुलिस ने एक नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने प्रियांशु खलखो, आशीष, राहुल व अन्य के खिलाफ धारा 70 (2) बीएनएस और पॉक्सो एकट की धारा 4(2),5 (जी) व 6 के तहत अपराध दर्ज किया और दोनों पीड़िताओं का एमएलसी कराया। जबकि दूसरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।

### एसपी बोले...हुआ है गैंगरेप

इस मामले में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शिकायत मिलते ही पुलिस को अपराध दर्ज कर एमएलसी कराना चाहिए था। इधर सरगुजा एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 29 अप्रैल को दोनों नाबालिग लड़कियों को अंबिकापुर लाया गया है।

### सीतापुर महिला उत्पीड़न मामला: एक आरोपी व विधि से संघर्षरत बालक हिरासत में

थाना सीतापुर क्षेत्र में महिला उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए एक आरोपी तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया है। मामले में वैधानिक प्रक्रिया के तहत जांच जारी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया की रिपोर्ट पर 26 अप्रैल 2026 को थाना सीतापुर में आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। प्रकरण दर्ज होने के बाद से पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मामले में पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना पुलिस ने बताया कि अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

### एफआईआर में देरी से पुलिस पर उठे सवाल

**घटना के दो दिन बाद मामला दर्ज होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत मिलते ही तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। देरी को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी देखी जा रही है।**

## सरगुजा संभाग में बोर्ड रिजल्ट जारी,बेटियों का दबदबा,टॉप-10 में नहीं बना स्थान

# 10वीं में 83.09 प्रतिशत व 12वीं में 80.56 प्रतिशत रिजल्ट...ज्योति साहू,आशीष केरकेट्टा जिला टॉपर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष अविभाजित सरगुजा संभाग से कोई भी छात्र स्टेट टॉप-10 में जगह नहीं बना पाया। हालांकि,दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लडक़ों से बेहतर रहा है। सरगुजा जिले में 10वीं का रिजल्ट 83.09 प्रतिशत तथा 12वीं का 80.56 प्रतिशत रहा। वहीं सूरजपुर में 10वीं का 82.75 व 12वीं का 86.46 प्रतिशत परिणाम दर्ज हुआ। बलरामपुर जिले में 10वीं का 84.63 व 12वीं का 84.29 प्रतिशत रिजल्ट रहा। कक्षा 10वीं में सरगुजा जिले में 7906 विद्यार्थी सफल हुए हैं। जिसमें प्रथम श्रेणी से 4133, द्वितीय श्रेणी 3634 व तृतीय श्रेणी से 139 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जबकि कक्षा 12वीं में 6397 विद्यार्थी सफल हुए हैं। जिसमें प्रथम श्रेणी 3491, द्वितीय श्रेणी 2792 व तृतीय श्रेणी से 114 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 10वीं में बलरामपुर जिले से 7686 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। प्रथम श्रेणी से 4510, द्वितीय श्रेणी से 2967 व तृतीय श्रेणी से 209 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 12वीं में बलरामपुर जिले से 5788 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। प्रथम श्रेणी से 3455, द्वितीय श्रेणी से 2253 व तृतीय श्रेणी से 80 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह सूरजपुर में 8224 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी से 4466, द्वितीय श्रेणी से 3560 व तृतीय श्रेणी से 198 विद्यार्थी उत्तिर्ण हुए हैं। कक्षा 12वीं में सूरजपुर जिले से 6975 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। प्रथम श्रेणी से 4147, द्वितीय श्रेणी से 2724 व तृतीय श्रेणी से 103 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

**सरगुजा में ज्योति साहू टॉपर :** सरगुजा जिले में 10वीं में ज्योति साहू ने 97.33 प्रतिशत अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर वेदिका राजवाड़े (96 प्रतिशत) और तीसरे स्थान पर यामिनी गेंडले (95.83 प्रतिशत) रहीं। 12वीं में बाबा आशीष केरकेट्टा ने 94.40 प्रतिशत अंक के साथ जिला टॉप किया। कैलाश कुमार (94 प्रतिशत) दूसरे व कोमल पटेल (93.80 प्रतिशत) तीसरे स्थान पर रहे।

**सूरजपुर में बेटियों का शानदार प्रदर्शन :** सूरजपुर जिले में दोनों परीक्षाओं में बालिकाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। 12वीं में लड़कियों का परिणाम लडक़ों से करीब 5.5 प्रतिशत अधिक रहा,जबकि 10वीं में यह अंतर लगभग 6.25 प्रतिशत का रहा। जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में 12वीं में 14 प्रतिशत व 10वीं में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

**हर्ष जायसवाल के उत्तीर्ण होने पर नगर में हर्ष सीजीबीएसई 10 वी में 94% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया**

सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत के छात्र हर्ष जायसवाल ने सीबीएससी के इम्तिहान में 94% अंक हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्र प्रयास रेसीडेंटल ब्लॉय स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ सीजीबीएसई बोर्ड में 94% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया उन्होंने अपने इस सफलता के लिए गुरुजन एव माता-पिता को श्रेय दिया है। छात्र के शानदार सफलता से पूरे लखनपुर में हर्ष का माहौल है। हर्ष जयसवाल पिता संतोष जायसवाल माता साधना जायसवाल के पुत्र हैं।

**बलरामपुर के टॉपर :** बलरामपुर में 10वीं में आर्यन गुप्ता (97 प्रतिशत) ने पहला स्थान प्राप्त किया। आराधना पटेल (96.83 प्रतिशत) दूसरे स्थान पर रहीं। 12वीं में प्रतिभा गुप्ता व स्नेहा कुशवाहा ने 94.80 प्रतिशत अंक के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया। दूसरे स्थान पर सोनू (94.20 प्रतिशत) रहे।

# विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में यूजीसी-जेआरएफ फेलोशिप का दे प्रशिक्षण : कुलपति

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो शिक्षा, परीक्षा, और अनुसंधान के मानको को सुनिश्चित करता है। ऐसे परीक्षा में विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के छात्र बजरंग देवांगन का चयन वीएच. डी. हेतु प्रतिष्ठित यूजीसी-जेआरएफ केलोशिप के लिए होना बहुत ही हर्ष की बात है। ये बातें विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं कुलपति प्रोफेसर राजेन्द्र लक्पाले ने छात्र बजरंग देवांगन को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कही। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सभी शिक्षको को निर्देश दिया की इस तरह की

सफलता भविष्य में सभी विभागों से विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। इसके लिए सतत प्रयाश करे और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे। उन्होंने आगे कहा की इस प्रकार की उपलब्धियां विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उक्तुष्टता एवं शोध संस्कृति को सुदृढ़ करती हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी ने छात्र बजरंग देवांगन को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने छात्र के उज्ज्वल भविष्य एवं शोध कार्य की सफलता की कामना की। छात्र बजरंग देवांगन ने जैव प्रौद्योगिकी में पीएच. डी. हेतु प्रतिष्ठित यूजीसी-जेआरएफ फेलोशिय प्राप्त की है। यह उपलब्धि विभाग के लिए पहली है। उनका शोध कार्य डॉ. अमृता कुमारी पांडा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी के मार्गदर्शन में संपादित किया जाएगा। शोध का विषय 'पादय वृद्धि प्रोत्साहक सूक्ष्मजीवों से युक्त जैव-फॉर्मुलेशनों की प्रभावशीलता का टमाटर एवं मिर्च फसलों के स्वास्थ्य पर, सरगुजा (छत्तीसगढ़) की लाल एवं जलोढ़ मिट्टी में अध्ययन' है, जो क्षेत्रीय कृषि उत्पादकता एवं सतत कृषि पद्धतियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

## नायकों को मिलेगा सम्मान : पद्म पुरस्कार 2027 हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस वर्ष 2027 के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री) के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च 2026 से आधिकारिक पोर्टल पर प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक व्यक्तियों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2027 निर्धारित की गई है। कार्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से देश के सुदूर वनांचल, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे गुमनाम नायकों को पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो समाज सेवा, कला, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग जैसे विविध क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं।

CMYK

# बड़े सालही में बेदखली बनाम पौधारोपण! ग्रामीणों की गुहार अनसुनी,वन विभाग की कार्रवाई जारी

## जनसुनवाई बिना वृक्षारोपण बड़े सालही में आदिवासियों ने उठाए सवाल

- पुश्तैनी जमीन पर संकट,200 साल से बसे ग्रामीणों पर बेदखली का खतरा
- वन विभाग की कार्रवाई से भड़का आक्रोश,बड़े सालही में ग्रामीणों का विरोध तेज
- गुहार के बाद भी नहीं रुकी कार्रवाई,बड़े सालही में जबरन पौधारोपण का आरोप
- पेड़ कटाई बनाम पौधारोपण...सरगुजा में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल
- कलेक्टर को आवेदन बेअसर? बड़े सालही में जारी बेदखली और पौधारोपण
- ग्रामीणों ने सुनाई पीड़ा,अशोक जायसवाल ने दिया आश्वासन,बड़े सालही विवाद गरमाया
- अधिकार बनाम वन विभाग,बड़े सालही में जमीन और अस्तित्व की लड़ाई

### वृक्षारोपण के नाम पर जबरन कार्रवाई का आरोप

ग्रामीणों ने वन विभाग पर यह आरोप लगाया है कि व्यावसायिक वृक्षारोपण के नाम पर उनकी जमीन खाली कराई जा रही है, उनका कहना है कि पहले उन्हें नोटिस देकर चेतावनी दी गई और अब बिना उनकी सहमति के सीधे जमीन पर पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया गया है, ग्रामीणों के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया न तो पारदर्शी है और न ही कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप दिखाई देती है, उन्हें न तो समुचित जानकारी दी गई और न ही किसी प्रकार की जनसुनवाई आयोजित की गई, जिससे यह कार्रवाई एकतरफा और जबरन प्रतीत होती है।

### पेड़ कटाई और पौधारोपण के विरोधाभास पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है,जिस पर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं,एक ओर सरगुजा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की खबरें सामने आती रही हैं,वहीं दूसरी ओर बड़े सालही में जबरन पौधारोपण किया जा रहा है,ग्रामीणों का कहना है कि यह विरोधाभास समझ से परे है,जहां पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पौधे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जगहों पर पेड़ों की कटाई जारी है। इससे वन विभाग की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

### ग्रामीणों की गुहार पर प्रशासन की चुप्पी

ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को आवेदन दिया था,जिसमें उन्होंने पुनर्वास प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी भी प्रकार की बेदखली और वृक्षारोपण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी,लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया, आवेदन देने के बावजूद न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही किसी प्रकार की जांच या संवाद की पहल की गई,इस चुप्पी ने ग्रामीणों के मन में प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना को और बढ़ा दिया है।

-राजन पाण्डेय-
कोरिया,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

कोरिया जिले के ग्राम बड़े सालही में इन दिनों एक ऐसा विवाद गहराता जा रहा है, जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली, आदिवासी अधिकारों और वन विभाग की गतिविधियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर ग्रामीण अपने पुश्तैनी निवास और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर जमीन खाली कराने की प्रक्रिया जारी है, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले ही जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर अपनी समस्याएं और आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन उनकी इस गुहार को अब तक कोई ठोस राहत नहीं मिली, उल्टा, वन विभाग द्वारा बिना जनसुनवाई और बिना पुनर्वास के पौधारोपण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे गांव में आक्रोश और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है।

### 200 वर्षों से निवास का दावा, अचानक बेदखली का दबाव

बड़े सालही के ग्रामीणों का दावा है कि वे पिछले लगभग 200 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, गांव में करीब 300 परिवार रहते हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 1000 के आसपास बताई जा रही है,यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल है और संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं,ग्रामीणों का आरोप है कि इन संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए वन विभाग द्वारा उन्हें बेदखल करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास के इस तरह की कार्रवाई उनके जीवन, आजीविका और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है।

### कांग्रेस नेता अशोक जायसवाल का दौरा,ग्रामीणों ने घेरकर बताई पीड़ा

मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेता अशोक जायसवाल बड़े सालही गांव पहुंचे,उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके आसपास इकट्ठा हो गए और अपनी समस्याएं बताने लगे,ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और यदि उन्हें इस तरह हटाया गया,तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा,उन्होंने यह भी बताया कि बिना पुनर्वास के बेदखली उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं होगी, अशोक जायसवाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मामले को कलेक्टर कोरिया के सामने उठाएंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।

### अधिकारों और आजीविका पर खतरा

ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला केवल जमीन का नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व और पहचान का है, उनकी आजीविका, रहन-सहन, संस्कृति और सामाजिक जीवन सब कुछ इसी जमीन से जुड़ा हुआ है, यदि उन्हें यहां से हटाया जाता है, तो वे न केवल अपने घर से वंचित होंगे, बल्कि अपनी परंपराओं और जीवन शैली से भी दूर हो जाएंगे, ऐसे में वे इस कार्रवाई को अपने मूल अधिकारों के खिलाफ मानते हैं और इसे रोकने की मांग कर रहे हैं।

### प्रशासन और वन विभाग पर बढ़ता दबाव

जैसे-जैसे यह मामला सामने आ रहा है, प्रशासन और वन विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है, स्थानीय लोग और ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि तत्काल इस कार्रवाई को रोका जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पुनर्वास की स्पष्ट और ठोस व्यवस्था की जाए।

### टकराव की स्थिति बनने की आशंका

लगातार अनदेखी और जबरन कार्रवाई के कारण गांव में आक्रोश बढ़ता जा रहा है,यदि समय रहते इस मामले का समाधान नहीं निकाला गया,तो यह विवाद और बढ़ सकता है और प्रशासन तथा ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है,स्थिति को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि प्रशासन संवाद का रास्ता अपनाए और सभी पक्षों को साथ लेकर समाधान निकाले।

### विकास बनाम अधिकार का संघर्ष

बड़े सालही का यह मामला अब केवल वृक्षारोपण या बेदखली तक सीमित नहीं रह गया है,बल्कि यह विकास और अधिकारों के बीच संतुलन का बड़ा प्रश्न बन गया है,एक ओर पर्यावरण संरक्षण और वन विकास की योजनाएं हैं,वहीं दूसरी ओर उन योजनाओं के कारण प्रभावित होने वाले लोगों के अधिकार और जीवन से जुड़े सवाल हैं,यदि इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बनाया गया,तो इस तरह के विवाद आगे भी सामने आते रहेंगे,अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे को किस तरह सुलझाता है और क्या ग्रामीणों को न्याय मिल पाता है या नहीं।

# कोरिया जिले का ऐतिहासिक गौरव: बोर्ड परीक्षाओं में रचा नया कीर्तिमान,प्रदेश की मेरिट सूची में बेटियों ने लहराया परचम

## हाई स्कूल परीक्षा में आंशिक कश्यप और आलिया परवीन ने राज्य के टॉप टेन में बनाया स्थान

- हायर सेकेंडरी में सोनहत की रागनी गुप्ता ने जिले में बनाया स्थान
- कलेक्टर कोरिया के शिक्षा के प्रति लगातार सजगता और प्रयासों का दिखा जोर

-संवाददाता-
कोरिया,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षा परिणामों में कोरिया जिले ने सफलता की एक नई इबारत लिखी है। जिले के शैक्षणिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब कक्षा 10वीं की राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) में जिले की दो मेधावी छात्राओं ने एक साथ स्थान बनाकर पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

### बेटियों ने रचा इतिहास

जिले के लिए गौरव का क्षण तब आया जब स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महलपारा (बैकुंठपुर) की छात्रा अंशिका कश्यप ने प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर की आलिया परवीन ने राज्य में 7वां स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इन छात्राओं की इस अभूतपूर्व उपलब्धि से न केवल उनके परिजनों में हर्ष व्याप्त है, बल्कि पूरे जिले का मस्तक गर्व से ऊँचा हो गया है।

### वनांचल विकासखण्ड सोनहत में भी लहराया सफलता का परचम

जिला मुख्यालय के साथ-साथ वनांचल विकासखण्ड सोनहत में भी परीक्षा परिणाम अत्यंत शानदार रहे। यहाँ की होनहार बेटी रागनी गुप्ता ने सर्वाधिक 96 प्रतिशत अंक अर्जित कर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। रागनी की इस विशेष उपलब्धि पर शिक्षा विभाग ने त्वरित उत्साह दिखाया। परीक्षा परिणाम जारी होते ही विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह, प्राचार्य देवदत्त सिंह के साथ रागनी गुप्ता के घर पहुँचे। उन्होंने रागनी को मिठाई खिलाई और मोमेंटो व पुष्प गुच्छ भेंट कर उसे सम्मानित किया। इस अवसर पर बीईओ अरविंद सिंह ने सोनहत की इस सफलता का श्रेय कलेक्टर कोरिया के कुशल मार्गदर्शन, जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग और स्थानीय शिक्षकों के कड़े परिश्रम को दिया।

### कलेक्टर वंदन त्रिपाठी के नेतृत्व और शिक्षकों के समर्पण का प्रतिफल

कोरिया जिले की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व को मुख्य आधार माना जा रहा है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक प्रयास किए गए। इस सफलता का वास्तविक श्रेय जिले के कर्मठ शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने प्रशासन के विजन को धरातल पर उतारा और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए मानसिक व विषयवार तैयार किया।

### 12वीं बोर्ड में कोरिया प्रदेश भर में अव्वल

उत्साह केवल 10वीं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी कोरिया जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। यह परिणाम दर्शाते हैं कि जिले की शिक्षण व्यवस्था अब और भी अधिक सशक्त और परिणामोन्मुखी हो चुकी है। जिले भर में आज जश्न का माहौल है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने सभी मेधावी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

### सोनहत विकासखण्ड के प्रमुख विद्यालयों का रिपोर्ट कार्ड

सोनहत क्षेत्र के दूरस्थ वनांचल स्कूलों से लेकर मुख्य केंद्रों तक,विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से शानदार सफलता प्राप्त की है

### शत-प्रतिशत (100%) परिणाम वाले स्कूल

हाई स्कूल बंशीपुरः कक्षा 10 वीं का परिणाम 100% रहा।

- स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल,कटघोड़ीः कक्षा 10 वीं और 12 वीं दोनों में 100% सफलता।

### हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरपुर

कक्षा 10 वीं और 12 वीं का परिणाम शत-प्रतिशत रहा।

- हाई स्कूल केशगवाः यहाँ भी विद्यार्थियों ने 100% परिणाम के साथ सफलता का परचम लहराया।
- कन्या हाई स्कूल सोनहत : छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम दर्ज किया।

### अन्य विद्यालयों का गौरवशाली प्रदर्शन

हायर सेकेंडरी स्कूल सोनहत : कक्षा 10 वीं में 96% और 12वीं में 96% अंक प्राप्त कर स्कूल ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी।

- स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम (सोनहत): यहाँ 10वीं का परिणाम 95% से अधिक रहा।
- हाई स्कूल पुसलाः यहाँ के विद्यार्थियों ने 94% परिणाम के साथ शानदार प्रदर्शन किया।
- हाई स्कूल कुशहा : ग्रामीण क्षेत्र के इस स्कूल ने 90% परिणाम देकर अपनी शैक्षणिक मजबूती साबित की।

### हांगकांग में बजेगा सरगुजा का नाम,आकाश दुबे टीम इंडिया में

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लिए यह बेहद गर्व और ऐतिहासिक क्षण है। सरगुजा वुडबॉल संघ से आकाश दुबे का चयन भारतीय वुडबॉल टीम में हुआ है। अब वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर हांगकांग इंटरनेशनल वुडबॉल चौंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 30 अप्रैल से 4 मई 2026 तक हांगकांग में आयोजित होगी, जहां आकाश दुबे भारतीय टीम का हिस्सा बनकर देश के लिए पदक जीतने का प्रयास करेंगे। आकाश दुबे का भारतीय टीम में चयन होने पर छत्तीसगढ़ वुडबॉल संघ के सचिव जितेंद्र पटेल,के.पी. सिंह, गौरव सिंह,सौरभ सिंहा, रजत सिंह समेत सरगुजा वुडबॉल संघ व सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ परिवार ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

**न्यायालय नायब तहसीलदार दरिमा, जिला-सरगुजा.छ0ग0**

रा0प्र0क0 /ब-121/2025-26

**ईश्तहार**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है - आवेदिका श्रीमति शीला यादव पति घुरन यादव निवासी ग्राम सखौली के द्वारा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के धारा 13 (3) एवं छ0ग0 जन्म/मृत्यु रजि0 नियम 2001 के नियम 09 (3) के अन्तर्गत अपने पिता स्व0 रामनाथ पिता स्व0 रघु के मृत्यु दिनांक 27/4/2006 को ग्राम सखौली में होना बतलाते हुये उनके जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 15/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
दरिमा
जिला-सरगुजा
सील

# पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान...अंबिकापुर की डॉ. भीष्मदेव साहू को राष्ट्रीय डॉ सी एम सिंह नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड-2026 से सम्मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पशु चिकित्सालय मंगारी प्रभारी एवं अनुभवी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. भीष्मदेव साहू (भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज़्ज़तनगर उ प्र से पीएचडी) को पशु चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान 'डॉ. सी एम सिंह एक्सीलेंस अवार्ड इन वेटरनरी साइंसेस -2026' से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के लिये देश और विदेश के 8 संस्थान के द्वारा मूल्यांकन किया गया. इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से पूरे प्रदेश, विशेषकर जिला बालोद, सरगुजा, उतई नगर एवं साहू समाज में हर्ष और गर्व का माहौल है। डॉ. साहू वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के पशु चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित उप संचालक कार्यालय से संबद्ध हैं और विकासखंड बतौली के मंगारी पशु चिकित्सालय प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग 15 वर्षों से राज्य शासन में पशु चिकित्सा सर्जन के रूप में कार्यरत हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

CMYK

# भ्रष्टाचार की नहर और बर्बादी का जलाशय : कदना में धंसी दीवार और टूटा गेट–किसानों का सवाल, 'सुशासन में कब मिलेगा पानी?

## कदना जलाशय बना भ्रष्टाचार की मिसाल.... गेट टूटा, दीवार धंसी,किसानों को पानी का इंतजार

- भ्रष्टाचार की नहरें,सूखे की आहट,कदना जलाशय की बदहाली से 400 हेक्टेयर जमीन संकट में
- एक साल से टूटा गेट,धंसी दीवार–कब जागेगा जल संसाधन विभाग?
- सुशासन के दावे पर सवाल,कदना में बर्बाद जलाशय,परेशान किसान
- नहरें बनीं मलबा,जलाशय बेकार,विभाग की चुप्पी से किसानों में आक्रोश
- कागजों में मरम्मत,जमीन पर बर्बादी,कदना जलाशय पर उठे भ्रष्टाचार के सवाल
- पानी बहने से पहले फूटा गुस्सा,कदना के किसान आंदोलन की तैयारी में
- ध्वस्त सिंचाई तंत्र गेट पोल जंग खा रहा,किसान बूंद-बूंद को मोहताज

स्पष्टीकरण या सवालों से बचने की कोशिश ? नहर में बहते पानी पर विभाग की सफाई से बढ़ा विवाद

-राजन पाण्डेय-

कोरिया/सोनहत,29 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिले में जल संसाधन विभाग इन दिनों अपने काम से कम और 'निराला सिस्टम' से ज्यादा चर्चा में है, सिस्टम ऐसा कि नाम भी निराला, काम भी निराला और नतीजा इतना निराला कि नहरें कागज पर बनती हैं, जमीन पर टूटती हैं और पानी किसानों तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार में बह जाता है, ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारों की एक ऐसी चेन दिखाई देती है, जहां जवाबदेही गायब और सुविधा-शुल्क का प्रवाह स्थायी बताया जा रहा है। बता दे की कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चन्दहा के कदना गांव में स्थित बंधापाठ जलाशय इन दिनों बदहाली,लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। कभी सैकड़ों किसानों की जीवनरेखा रहा यह जलाशय आज खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। जल संसाधन विभाग की अनदेखी के कारण यहां का वेस्ट वियर (अतिप्रवाह निकास) का गेट पोल टूटकर गिर चुका है और दीवार धंस गई है। चिंताजनक बात यह है कि इस गंभीर स्थिति को एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन विभाग अब तक मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।

### जिम्मेदार अधिकारी का नाम भी 'निराला' है और कार्यप्रणाली भी उतनी ही निराली

कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर क्षेत्र में जल संसाधन विभाग इन दिनों अपने कामकाज को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है, विभाग में कथित तौर पर 'निराला सिस्टम' चलने की चर्चा जोर पकड़ रही है, जहां जिम्मेदार अधिकारी का नाम भी 'निराला' है और कार्यप्रणाली भी उतनी ही निराली नजर आ रही है, लंबे समय से एक ही क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी पर आरोप है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने में अधिक रुचि ले रहे हैं, नहर निर्माण और जलाशयों के रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च दिखाए जा रहे हैं,लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है, बताया जा रहा है कि बैकुण्ठपुर क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जलाशयों और नहरों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों पर खर्च की जा चुकी है, इसके बावजूद नहरों की हालत बदतर बनी हुई है,कई जगहों पर नहरें टूट चुकी हैं,कहीं कंक्रीट बह गया है तो कहीं निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, ग्रामीणों का कहना है कि नहरों का निर्माण कागजों में पूरा दिखा दिया जाता है,जबकि वास्तविकता में गुणवत्ता का अभाव साफ नजर आता है,हालात ऐसे हैं कि पानी खेतों तक पहुंचने के बजाय बीच रास्ते में ही बह जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों और किसानों के बीच यह चर्चा आम हो गई है कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता का अभाव है और निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं, 'निराला सिस्टम' अब एक प्रतीक बन चुका है–ऐसी व्यवस्था का, जहां जवाबदेही कम और लापरवाही ज्यादा दिखाई देती है, सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े बजट के बावजूद न तो नहरें टिक पा रही हैं और न ही जलाशयों की स्थिति सुधर रही है, कुल मिलाकर,जल संसाधन विभाग की कार्यशैली ने क्षेत्र में असंतोष का माहौल बना दिया है,यदि समय रहते इन आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह 'निराला सिस्टम' किसानों के लिए और भी भारी पड़ सकता है।

### एक साल से टूटा गेट,धंसी दीवार–फिर भी मौन विभाग

जलाशय के वेस्ट वियर का गेट पोल पिछले एक वर्ष से टूटा हुआ है और दीवार भी कई जगहों से धंस चुकी है, हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय से यह स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन जल संसाधन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, आने वाले मानसून के मद्देनजर यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो बारिश का पानी जलाशय में ठहरने के बजाय सीधे बह जाएगा,इसका सीधा असर कदना और नावाटोला के सैकड़ों किसानों पर पड़ेगा,जिनकी खेती पूरी तरह इस जलाशय पर निर्भर है।

### मानसून से पहले बढ़ी किसानों की चिंता

मानसून आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है,और ऐसे में कदना जलाशय की वर्तमान स्थिति किसानों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गई है,यदि समय रहते गेट और दीवार की मरम्मत नहीं होती, तो बारिश का पानी जलाशय में ठहरने के बजाय सीधे बह जाएगा, इससे न केवल जलाशय की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, बल्कि कदना, नावाटोला और आसपास के गांवों के लगभग 200 किसानों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है। करीब 400 हेक्टेयर कृषि भूमि सूखे की चपेट में आ सकती है।

### नहरें भी बनीं भ्रष्टाचार की मिसाल

स्थानीय किसानों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जलाशय से जुड़ी नहरों की हालत भी बेहद खराब है, मरम्मत के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं,लेकिन धरातल पर नतीजा शून्य नजर आता है। कई स्थानों पर नहरें पूरी तरह टूट चुकी हैं, तो कहीं कंक्रीट की संरचना हवा में लटकती दिखाई दे रही है, नहरों के नीचे की जमीन गहरे खड्डों में तब्दील हो चुकी है, जिससे यह पूरा सिस्टम किसी भी समय पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है,कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 'यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सीधा-सीधा भ्रष्टाचार है, घटिया निर्माण और मरम्मत कार्यों के कारण आज पूरी सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है। '

### 400 हेक्टेयर सिंचाई पर संकट,200 किसान प्रभावित

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार,इस जलाशय से करीब 200 किसान लाभान्वित होते थे और लगभग 400 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है,कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने आरोप लगाया कि नहरों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई है, उन्होंने कहा कि नई बनी नहरें भी कुछ ही समय में टूटने लगी हैं, जो स्पष्ट रूप से घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं।

### नहरों की हालत–जमीन में धंसी,हवा में लटकी संरचना

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तस्वीरें इस पूरे मामले की भयावहता को उजागर करती हैं, कंक्रीट की मजबूत मानी जाने वाली नहरें अब कई जगहों पर हवा में लटक रही हैं, जबकि नीचे की जमीन गहरे खड्डों में तब्दील हो चुकी है। भारी-भरकम कंक्रीट के टुकड़े मलबे की तरह बिखरे पड़े हैं, यह दृश्य किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं, बल्कि लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम प्रतीत होता है, ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल निर्माण में खामियों का मामला नहीं, बल्कि 'अपराधिक लापरवाही' है।

**गेज बांध और अन्य जलाशयों का भी यही हाल**- यह समस्या केवल कदना जलाशय तक सीमित नहीं है,सोनहत क्षेत्र में स्थित गेज बांध,तन्जरा जलाशय और नाटवाही जलाशय की स्थिति भी लगभग ऐसी ही बताई जा रही है, हाल ही में गेज बांध की बदहाली भी चर्चा में रही, जिससे यह साफ होता है कि जल संसाधन विभाग पूरे जिले में अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल साबित हो रहा है, पंच संघ के अध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी का कहना है कि 'हर साल मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति होती है और किसानों को सिर्फ धोखा मिलता है। जिले के सभी जलाशयों और नहरों के कार्यों की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। '

**एसी कमरों में अधिकारी,धूप में जूझता किसान**- ग्रामीणों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश है कि विभागीय अधिकारी मौके पर आकर स्थिति का जायजा लेने तक की जरूरत नहीं समझ रहे, उनका आरोप है कि अधिकारी केवल दफ्तरों तक सीमित हैं, जबकि किसान अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है, पिछले वर्ष भी इस समस्या को उठाया गया था, लेकिन विभाग के स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई, परिणामस्वरूप स्थिति और बदतर हो गई है।

**एसडीओ पर सवाल—'चेंबर मोह' में फंसा विभाग?**-स्थानीय लोगों ने जल संसाधन विभाग के एसडीओ निराला की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि वर्षों से गेट पोल जमीन पर पड़ा जंग खा रहा है, लेकिन अधिकारी ने इसकी सुध लेने की जहमत तक नहीं उठाई, ग्रामीणों के अनुसार, यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं,बल्कि विभागीय उदासीनता और जवाबदेही की कमी का उदाहरण है, इससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है,बल्कि किसानों का भरोसा भी टूट रहा है।

### जनप्रतिनिधियों और किसानों की चेतावनी

पुष्पेंद्र राजवाड़े ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि एक माह के भीतर जलाशय और नहरों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ,तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की भी बात कही है, वहीं, युवा किसान कुलदीप कुमार ने कहा कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ,तो इस साल खेती करना मुश्किल हो जाएगा,पंच संघ अध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी ने जिले के सभी जलाशयों और नहरों के मरम्मत कार्यों की जांच की मांग की है,जबकि जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अनित दुबे ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।

### उठते बड़े सवाल...

- एक साल से टूटी संरचनाओं पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?
- मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता की जांच कौन करेगा?
- किसानों की आजीविका के साथ हो रहे इस खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन?
- क्या 'सुशासन' के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं?

### जवाबदेही तय हो,तभी बचेगी खेती

कदना जलाशय की यह स्थिति केवल एक गांव या क्षेत्र की समस्या नहीं है,बल्कि पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है,यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर न केवल किसानों की आजीविका पर पड़ेगा, बल्कि क्षेत्र की कृषि व्यवस्था भी गंभीर संकट में आ जाएगी,अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है या फिर किसान आंदोलन के रास्ते पर उतरने को मजबूर होते हैं।

## राजन पाण्डेय बने प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष

-संवाददाता-

रायपुर/कोरिया,29 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी प्रखर लेखनी और विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाले युवा पत्रकार राजन पाण्डेय को एक बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रेस और मीडिया जगत के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाली प्रतिष्ठित संस्था 'प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन' (नई दिल्ली) ने छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष (सरगुजा संभाग) नियुक्त किया है।

### संस्थापक के अनुमोदन और प्रस्ताव पर हुई नियुक्ति

यह महत्वपूर्ण नियुक्ति संस्था के प्रदेश पदाधिकारियों की विशेष बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव और संस्थापक मनोज पाण्डेय के अंतिम अनुमोदन के उपरांत की गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने राजन पाण्डेय की पत्रकारिता के प्रति अटूट निष्ठा,संगठन के प्रति समर्पण और मीडियाकर्मियों की समस्याओं को मुखरता से उठाने को देखते हुए यह विश्वास जताया है।

### संगठन को मिलेगी नई मजबूती

राजन पाण्डेय की कार्यकुशलता और जमीनी स्तर पर उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से संगठन को प्राप्त होगा। जानकारों का मानना है कि उनकी इस नियुक्ति से न केवल सरगुजा संभाग, बल्कि पूरे प्रदेश में संगठन की जड़ें और अधिक मजबूत होंगी। इस नई जिम्मेदारी की घोषणा के बाद पत्रकार साथियों, गणमान्य नागरिकों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

### इनका कहना है...

*'संगठन ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूँगा, मेरा प्राथमिक उद्देश्य छत्तीसगढ़ के हर छोटे-बड़े पत्रकार की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुँचाना और उनकी आवाज को सशक्त मंच प्रदान करना है। '*

राजन पाण्डेय
प्रदेश उपाध्यक्ष,प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन

# हीटवेव में बच्चों की परीक्षा...क्या मुख्यमंत्री का आदेश केवल निजी स्कूलों तक सीमित?

# एमसीबी में समर कैंप पर बड़ा सवाल,आदेश और वास्तविकता के बीच टकराव

## हीटवेव में समर कैंप : मनेन्द्रगढ़ के आत्मानंद स्कूल में आदेशों की अनदेखी,बच्चों की सेहत पर संकट

- भीषण गर्मी में भी खुला स्कूल क्या सरकार का अवकाश आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित
- लू के बीच प्रतियोगिता एमसीबी में शिक्षा विभाग ने बच्चों को झोंका तपती धूप में
- सुबह 8 से शाम 4 तक बच्चे स्कूल में समर कैंप बना जोखिम,अभिभावकों में आक्रोश
- सरकारी आदेश धरे रह गए,शासकीय स्कूलों में जारी गतिविधियां–जवाबदेही पर सवाल
- क्या नियम सिर्फ निजी स्कूलों के लिए...शासकीय संस्थानों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
- बजट खर्च या बच्चों की कीमत...भीषण गर्मी में प्रतियोगिताओं पर गहराया विवाद

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़/एमसीबी,29 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है,तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय हालात ऐसे बन रहे हैं कि सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो चुका है, इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं इस घोषणा के दौरान स्पष्ट किया था कि छात्रों की सेहत के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा,लेकिन एमसीबी जिले से सामने आई स्थिति इन दावों के ठीक विपरीत नजर आती है,यहां शिक्षा विभाग द्वारा भीषण गर्मी के बीच ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं और समर कैंप का आयोजन कराया जा रहा है, जिससे न केवल आदेशों की अनदेखी का मामला सामने आया है,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं।

### तपती दुपहरी में समर कैंप का आयोजन बच्चों की मजबूरी या व्यवस्था की लापरवाही

जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के आत्मानंद स्कूल सहित अन्य शासकीय स्कूलों में आयोजित किए जा रहे समर कैंप में बच्चों को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह वही समय है जब तापमान अपने चरम पर होता है और लू का प्रभाव सबसे अधिक रहता है,

### सरकारी आदेशों की अनदेखी क्या नियम केवल कागजों तक सीमित?

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश स्पष्ट रूप से सभी प्रकार के विद्यालयों पर लागू था,इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि शासकीय स्कूलों को किसी प्रकार की छूट दी गई है, इसके बावजूद एमसीबी जिले में न केवल समर कैंप आयोजित किया जा रहा है, बल्कि इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, यह स्थिति यह संकेत देती है कि आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, यदि शासन के निर्देशों का पालन कराने वाली एजेंसियां ही उनका पालन नहीं करेंगी, तो अन्य संस्थानों से पालन की अपेक्षा करना कठिन हो जाता है,यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या सरकार के आदेश केवल 'टेबल आदेश' बनकर रह गए हैं–जिनका उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरी करना है, न कि वास्तविक क्रियान्वयन।

### क्या आदेश केवल निजी स्कूलों पर लागू?

इस पूरे घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है– क्या स्कूल बंद करने का आदेश केवल निजी स्कूलों के लिए था? यदि ऐसा नहीं है, तो फिर शासकीय स्कूलों में प्रतियोगिताएं क्यों आयोजित की जा रही हैं? क्या शिक्षा विभाग को इस आदेश से छूट प्राप्त है? यह स्थिति दोहरे मापदंड की ओर इशारा करती है, जहां नियमों का पालन चयनात्मक तरीके से किया जा रहा है, इससे न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है,बल्कि यह भी संकेत मिलता है कि व्यवस्था के भीतर समन्वय और जवाबदेही की कमी है।

एक ओर प्रशासन आम नागरिकों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मासूम बच्चों को प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के नाम पर स्कूल बुलाया जा रहा है, यह स्थिति सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जोखिम लेने जैसी प्रतीत होती है, अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों को इतनी देर तक गर्मी में रोकना खतरनाक है, कई अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया है कि बच्चों को प्रतियोगिता और प्रमाणपत्र के नाम पर आकर्षित किया जा रहा है,जिससे वे मजबूरी में अपने बच्चों को भेज रहे हैं।

### हीटवेव की चेतावनी और स्वास्थ्य जोखिम

मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है,जिसमें विशेष रूप से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी गई है,चिकित्सकों के अनुसार, इस तरह की गर्मी में बच्चों को लंबे समय तक बाहर या गर्म वातावरण में रखने से हीट स्ट्रोक,डिहाइड्रेशन, चक्कर और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, बच्चों की शारीरिक क्षमता वयस्कों की तुलना में कम होती है, जिससे वे गर्मी के प्रभाव को जल्दी झेलते हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षित वातावरण में रखना अत्यंत आवश्यक होता है, इन सभी चेतावनियों के बावजूद यदि बच्चों को सुबह से शाम तक स्कूल में रोका जा रहा है, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर जोखिम उठाने जैसा है।

### शिक्षा विभाग की भूमिका पर सवाल

इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है, एक तरफ विभाग सरकार के आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, वहीं दूसरी तरफ वही विभाग इन आदेशों की अनदेखी करता नजर आ रहा है, यह स्थिति या तो विभागीय लापरवाही को दर्शाती है या फिर जानबूझकर नियमों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति को, कुछ स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं का आयोजन वार्षिक बजट खर्च करने और कागजी उपलब्धियां दिखाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, यदि यह आरोप सही हैं, तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता वितीय औपचारिकताओं को दी जा रही है।

### अभिभावकों और समाज में बढ़ता आक्रोश

इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, लोगों का कहना है कि जब सरकार ने स्पष्ट रूप से स्कूल बंद करने का आदेश दिया है, तो बच्चों को स्कूल बुलाना पूरी तरह अनुचित है, अभिभावकों का यह भी कहना है कि यदि इस दौरान किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है,तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि समर कैंप का उद्देश्य बच्चों का विकास होना चाहिए,न कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डालना जहां उनकी सेहत खतरे में पड़ जाए।

### प्रशासन की चुप्पी और जवाबदेही का अभाव

इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है–क्या प्रशासन इस मामले से अनजान है, या फिर जानबूझकर अनदेखी कर रहा है? यदि प्रशासन को जानकारी है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, यह न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है,बल्कि यह भी संकेत देती है कि जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया कमजोर पड़ रही है।

### कौशल विकास या औपचारिकता का दबाव

समर कैंप और ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता और कौशल को बढ़ावा देना होता है,लेकिन जब इन्हें भीषण गर्मी में आयोजित किया जाता है, तो उनका उद्देश्य ही बदल जाता है,ऐसे आयोजनों में बच्चों की भागीदारी स्वैच्छिक होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह आयोजन बच्चों के विकास से अधिक औपचारिकता और दबाव का रूप लेते नजर आ रहे हैं।

### तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत

मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आवश्यक हो गया है कि जिला प्रशासन और उच्च अधिकारी तत्काल हस्तक्षेप करें, ऐसे आयोजनों को तुरंत रोका जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी भी स्थिति में बच्चों की सुरक्षा से समझौता न हो, साथ ही,इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि एक स्पष्ट संदेश जाए कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

### बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि

एमसीबी जिले का यह मामला केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, जब सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्णय लेती है,तो उसका पालन करना हर स्तर पर अनिवार्य होता है, यदि यही पालन नहीं होगा,तो न केवल आदेशों की विश्वसनीयता खत्म होगी, बल्कि बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी,अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों की सेहत और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस पहल की जाती है।

## कोयला माफिया पर प्रशासन का शिकंजा...

# रेत की आड़ में कोयले की तस्करी हुई नाकाम,एमसीबी में खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, ट्रैक्टर जब्त

संवाददाता-
एमसीबी,29 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
जिले में अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लगातार मिल रही शिकायतों और मीडिया में सामने आई खबरों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और खनिज संपदा की अवैध लूट पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया,18 अप्रैल 2026 को प्रकाशित एक खबर में यह खुलासा हुआ था कि मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र से रात के अंधेरे में अवैध कोयला उत्खनन कर उसे पड़ोसी राज्यों में खपाया जा रहा है, इस गंभीर सूचना को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर के निर्देशन में खनिज विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की रणनीति बनाई। एमसीबी में खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्रशासन सतर्क और सक्रिय रहे, तो अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है, रेत की आड़ में कोयला तस्करी का यह मामला भले ही छोटा प्रतीत हो, लेकिन यह एक बड़े नेटवर्क की ओर संकेत करता है, अब देखना होगा कि प्रशासन इस कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाता है और क्या आने वाले दिनों में इस पूरे तंत्र पर पूरी तरह से शिकंजा कस पाता है।

### रात में चला विशेष अभियान, पोड़ी थाना क्षेत्र में कार्रवाई...

22 अप्रैल 2026 की रात लगभग 8 बजे चिरमिरी के पोड़ी थाना क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा विशेष छापामार अभियान चलाया गया, इस दौरान एक संदिग्ध ट्रैक्टर (सीजे16 सीआर 0241) को रोककर जांच की गई, जिसमें ट्रॉली में ऊपर से रेत डालकर कोयले को छिपाया गया था। पहली नजर में यह सामान्य रेत परिवहन जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब टीम ने बारीकी से जांच की तो रेत की परत के नीचे अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा कोयला बरामद हुआ।

### रेत की परत में छिपा था कोयला, तस्करों की चाल नाकाम

तस्करों ने जांच एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए कोयले को रेत से ढंकने का तरीका अपनाया था, ताकि सतही जांच में यह सामान्य रेत परिवहन लगे, लेकिन संयुक्त टीम की सतर्कता और सूझबूझ के चलते यह चाल सफल नहीं हो सकी, जांच के दौरान पूरा मामला उजागर हो गया और मौके पर ही ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया।

**जब्त ट्रैक्टर थाना परिसर में,आगे की कार्रवाई जारी**–कार्रवाई के बाद जब्त किए गए ट्रैक्टर को सुरक्षा की दृष्टि से पोड़ी थाना परिसर में खड़ा कराया गया है,प्रकरण में संबंधित आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है,खनिज विभाग और पुलिस विभाग मिलकर मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं,ताकि इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके।

**प्रशासन का सख्त संदेश : अवैध खनन बर्दाश्त नहीं**– जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन,परिवहन और तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, अधिकारियों का कहना है कि जिले की खनिज संपदा की सुरक्षा प्राथमिकता है और इसके दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी,इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

**रात्रिकालीन निगरानी और तेज होगी**– प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में रात के समय विशेष निगरानी बढ़ाई जाएगी,संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जाएगी, छापामार कार्रवाई को और तेज किया जाएगा,ताकि अवैध खनन और तस्करी की गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

**खनिज संपदा की लूट पर रोक की दिशा में कदम**– एमसीबी जिला खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है, और यहां अवैध खनन लंबे समय से चिंता का विषय रहा है,प्रशासन की यह कार्रवाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे न केवल तस्करी पर रोक लगेगी,बल्कि शासन को होने वाले राजस्व नुकसान को भी कम किया जा सकेगा।

## सूरजपुर : चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र से दर्दनाक घटना....

# घर में भीषण आग,अधेड़ की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत,उमझर गांव में मातम

संवाददाता-
सूरजपुर,29 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
जिले के चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उमझर से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, मोहरसोप चौकी क्षेत्र के उमझर गांव में एक घर में अचानक लगी भीषण आग ने एक अधेड़ की जान ले ली,मृतक की पहचान ईश्वर सिंह आयाम के रूप में हुई है, जो गांव के स्कूल पारा के निवासी और ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव रह चुके थे,यह घटना इतनी भयावह थी कि कुछ ही पलों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और ईश्वर सिंह आयाम को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। बता दे की सूरजपुर के उमझर गांव की यह घटना बेहद दर्दनाक और चेतावनी देने वाली है,एक छोटी सी चूक ने एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया, अब जरूरी है कि प्रशासन इस मामले में गंभीरता दिखाए,जांच पूरी कर सच्चाई सामने लाए और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करे,यह हादसा न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक भी है कि सतर्कता और सुरक्षा उपायों की अनदेखी कभी भी भारी पड़ सकती है।

**आग की चपेट में आए ईश्वर सिंह, मौके पर ही मौत**–बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात कारण से घर में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलती चली गई और घर के अंदर मौजूद ईश्वर सिंह आयाम उसकी चपेट में आ गए,प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से भड़की कि जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते और मदद के लिए पहुंचते,तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे,ईश्वर सिंह आग की लपटों में घिर गए और उनकी मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। यह दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा, वह सन्न रह गया।

**गांव में पसरा मातम,सम्मानित व्यक्ति थे ईश्वर सिंह**– इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे उमझर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ईश्वर सिंह आयाम गांव में एक जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, उनकी अचानक और इस तरह की दर्दनाक मौत से ग्रामीण स्तब्ध हैं। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव का माहौल गमगीन बना हुआ है।

**ग्रामीणों की मांग निष्पक्ष जांच और मुआवजा**–घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए, साथ ही, मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजा प्रदान करने की भी मांग की गई है, ताकि इस कठिन समय में परिवार को सहारा मिल सके, ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर करती हैं।

### ग्रामीणों ने किया बचाव का प्रयास,लेकिन नहीं बच पाई जान...

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई,ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया,लोगों ने पानी और अन्य साधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर के अंदर फंसे ईश्वर सिंह को बाहर निकालना संभव नहीं हो सका,कुछ ही देर में पूरा घर जलकर खाक हो गया और अंदर मौजूद ईश्वर सिंह की मौत हो गई।

### पुलिस मौके पर पहुंची,जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही मोहरसोप पुलिस चौकी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची,पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पंचनामा कार्रवाई पूरी की,मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है,प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, हालांकि शॉर्ट सर्किट या घरेलू कारणों से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, पुलिस का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा।

**अग्नि सुरक्षा पर फिर उठे सवाल**– यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, छोटी सी चूक या तकनीकी खराबी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है,ऐसे में जरूरत है कि घरों में विद्युत सुरक्षा की जांच नियमित हो, आग से बचाव के प्राथमिक उपायों की जानकारी लोगों को दी जाए,आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जाए।

CMYK

# नाना पाटेकर को बनाना चाहते थे खलनायक...अनिल कपूर हड़पना चाहते थे रोल,कैसे संजय दत्त बने बल्लू गैंगस्टर?

**संजय दत्त की फिल्म खलनायक 1993 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म थी। हालांकि, सुभाष घई उन्हें नहीं, बल्कि नाना पाटेकर को यह रोल देना चाहते थे। कैसे संजय दत्त की झोली में गिरी खलनायक**

संजय दत्त एक बार फिर से खलनायक रिटर्न्स के साथ फिल्मी पर्दे पर खूंखार विलेन बनकर लौट रहे हैं। बीते दिनों ही फिल्म का पहला टीजर और कुछ पोस्टर्स मेकर्स ने रिलीज किए थे, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया था। हालांकि, आपको यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई कल्ट फिल्म खलनायक के लिए संजय दत्त निर्देशक सुभाष घई की पहली चॉइस नहीं थे, बल्कि वह तो नाना पाटेकर से यह रोल करवाना चाहते थे। खलनायक के खूंखार विलेन बल्लू का रोल आखिर संजय दत्त की झोली में कैसे आ गिरा,इसके पीछे का दिलचस्प किस्सा खुद सुभाष घई ने सुनाया था।

### नाना पाटेकर के साथ बनाना चाहते थे खलनायक

परदेस और राम लखन जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाले सुभाष घई ने रेडिफ डॉट कॉम को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह खलनायक संजय दत्त के साथ नहीं, बल्कि नाना पाटेकर के साथ बनाने की प्लानिंग कर रहे

थे। सुभाष घई ने कहा था जब फिल्म का पहला नया ड्राफ्ट रेडी हुआ था,तो मैंने सबसे पहले नाना पाटेकर को फोन मिलाया था। उन्होंने कहानी सुनी और उन्हें पसंद भी आई। मैंने उस वक्त ये सोचा था कि मैं इसे कम बजट की एक आर्ट फिल्म के रूप में बनाऊंगा। लेकिन जब मैंने यह कहानी अपने राइटर्स को सुनाई, तो मेरे साथ के लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे इस कहानी के साथ एक कमर्शियल फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है।

### अनिल कपूर खलनायक में निभाना चाहते थे यह किरदार

जिस वक्त सुभाष घई खलनायक बनाने का मन बना रहे थे, उस दौर में वह अनिल कपूर के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा रहे थे। दोनों ने पहली बार फिल्म मेरी जंग में काम किया था। इसके बाद इस जोड़ी ने कर्मा, राम लखन और ताल जैसी फिल्मों में साथ काम किया। सुभाष घई ने इस इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि जब अनिल कपूर को खलनायक की स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, तो वह सीधे निर्देशक के घर पहुंच गए और उन्होंने खलनायक में बल्लू बलराम का किरदार अदा करने की इच्छा जताई। हालांकि, सुभाष घई ने उन्हें खलनायक में कास्ट करने से मना करते हुए यह कह दिया कि उन पर यह रोल सूट नहीं करेगा।

### इस फिल्म की वजह से संजय दत्त को मिली खलनायक

सुभाष घई ने बातचीत में यह भी खुलासा किया कि उन्होंने संजय दत्त को ही खलनायक के रोल के लिए क्यों चुना। निर्देशक ने कहा, मैंने साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म विधाता में संजय दत्त के साथ काम किया था। मुझे लगा कि वह इस रोल के लिए परफेक्ट होंगे। मैंने संजू को कॉल किया और उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई। उन्होंने मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर खुशी-खुशी खलनायक में बल्लू बलराम का किरदार निभाने के लिए हामी भर दी। संजय दत्त द्वारा निभाए गए इस किरदार ने उन्हें अपनी रोमांटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलने में काफी मदद की।

साल 1993 में आई इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिका में थे। यह गोविंदा की आंखें के बाद उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

# यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी,उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था...

मालूम हो कि बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता पाने वाली फिल्म हनुमान ने एक छोटी फिल्म के तौर पर शुरुआत की और दुनिया भर में ज़बरदस्त कलेक्शन करके नए रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म से सभी एक्टर्स को अच्छी पहचान मिली। हालांकि, एक्ट्रेस फारिया अब्दुल्ला का यह कमेंट अब वायरल हो रहा है कि उन्होंने यह ब्लॉकबस्टर मौका गंवा दिया। फारिया, जिन्होंने हाल ही में अपनी नई फिल्म वजह्रू सिंघम (1 मई को रिलीज़) के प्रमोशन में हिस्सा लिया, ने अपने करियर के बारे में दिलचस्प बातें शेयर कीं। उन्होंने कहा कि जथिरत्नालु के बाद जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो कहानी चुनने की सही समझ न होने की वजह से वह हनुमान जैसा अच्छा प्रोजेक्ट चूक गईं। उस समय, मुझे स्क्रिप्ट्स को एवैल्यूएट करना नहीं आता था। मैंने एक अच्छी कहानी पहचानने में गलती की। सच कहूं तो, मैंने बिना सोचे-समझे नहीं कह दिया। अब, फिल्म का रिजल्ट देखने के बाद,मैं बहुत दुखी हूं, फारिया ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वह जब भी डायरेक्टर प्रशांत वर्मा और हीरो तेजा सज्जा से मिलेंगी, तो यह बात उन्हें याद रहेगी। उस समय, मेरे पास सच में दिमाग नहीं था। मैंने बिना सोचे-समझे नहीं कह दिया। असल में, मुझे नहीं पता कि कहानी को कैसे जज किया जाता है।

उन्होंने कहा कि अब से वह अपने करियर में कहानियां चुनते समय सोच-समझकर कदम उठाएंगी। फारिया ने जो रोल छोड़ा था, वह आखिरकार अमृता अय्यर को मिल गया और उस फिल्म से उन्हें नेशनल पहचान मिली। यह उदाहरण एक बार फिर साबित करता है कि इंडस्ट्री में एक मौका जो एक इंसान ने छोड़ दिया, वह दूसरे के लिए वरदान बन सकता है। फिलहाल, फारिया ने अपनी सारी उम्मीदें फिल्म गायपड्डा सिंहम पर टिका दी हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस फिल्म से उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी और उनके करियर को नई रफ्तार मिलेगी। देखते हैं आगे क्या होता है।

# राजपाल यादव की बल्ले-बल्ले, जेल से बाहर आकर मिली बड़ी फिल्म,19 साल बाद सलमान खान संग करेंगे वापसी

कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म में शामिल होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते दिनों अभिनेता राजपाल यादव का नाम प्रोफेशनल करियर से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में जेल की हवा खाने वाले राजपाल का एक्टिंग करियर अब पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि राजपाल यादव को हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म हाथ लगी है। इस मूवी के जरिए राजपाल करीब 19 साल बाद भाईजान के साथ पर्दे पर वापसी करते हुए नजर आएंगे।

### सलमान की मूवी में राजपाल की एंट्री

बीते दिनों पहले एक अवॉर्ड शो में राजपाल यादव का चेक बाउंस मामले में मजाक उड़ाया गया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर सलमान ने राजपाल के समर्थन में ट्वीट कर हर किसी को हैरान कर दिया था, तब से ये सुर्खियां तेज हो गई कि आने वाले समय में कॉमेडियन एक्टर भाईजान की फिल्म में दिखाई देंगे। अब खबर आ रही है कि साउथ फिल्म निर्देशक वामशी पेडिपल्ली संग सलमान खान की मोस्ट अवेटेड अनटाइटल फिल्म एसवीएसी 63 में राजपाल की एंट्री हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की इस अपकमिंग एक्शन थ्रिलर में राजपाल यादव अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि का एलान होना बाकी है। सलमान और नयनतारा की इस आने वाली फिल्म की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई है और अब राजपाल यादव का नाम सामने आने के बाद मूवी की चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि बतौर कलाकार राजपाल यादव पिछली बार सलमान खान के साथ 19 साल पहले 2007 में रिलीज होने वाली कॉमेडी फिल्म पार्टनर में नजर आए थे। इससे पहले वह मुझसे शादी करोगी जैसी मूवी में भी भाईजान के साथ काम कर चुके हैं। मालूम हो कि जेल से बाहर आने के बाद राजपाल ने हाल ही में रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला से वापसी की है।

### कब रिलीज होगी सलमान और नयनतारा की फिल्म

निर्देशक वामशी पेडिपल्ली और निर्माता दिल राजू की अपकमिंग फिल्म के जरिए पहली बार पर्दे पर दर्शकों को सलमान खान और नयनतारा की जोड़ी देखने को मिलेगी। गौर करें इन दोनों की इस बहुचर्चित फिल्म की रिलीज डेट की तरफ तो वह ईद 2027 है।

# रूपाली गांगुली ने आलिया भट्ट के मिलान फैशन वीक आउटफिट पर आलोचनात्मक पोस्ट फिर से शेयर किया

रूपाली गांगुली ने एक पोस्ट को रीशेयर करके ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी है, जिसमें आलिया भट्ट और मिलान फैशन वीक में पहने उनके आउटफिट की बुराई की गई थी। अनुपमा के लिए मशहूर एक्टर ने 27 अप्रैल को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर वीडियो रीपोस्ट किया। शेयर किए गए वीडियो में कथित तौर पर आलिया भट्ट के हालिया फैशन अपीयरेंस में जानवरों से मिले लेदर के कथित इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया था। हालांकि रूपाली ने कोई लिखा हुआ कैप्शन या पर्सनल कमेंट नहीं किया, लेकिन कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस रीपोस्ट को एक इनडायरेक्ट बयान के तौर पर देखा, खासकर जानवरों की भलाई के कामों के लिए उनके जाने-माने सपोर्ट को देखते हुए। अभी तक, आलिया भट्ट ने रीपोस्ट को लेकर हो रही चर्चा पर पब्लिकली कोई जवाब नहीं दिया है। आलिया हाल ही में गुच्ची के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर के तौर पर मिलान में गुच्ची के प्रिमावेरा शो में शामिल हुई थीं। यह इवेंट लेबल के लिए क्रिएटिव डायरेक्टर डेम्ना के डेब्यू प्रेजेंटेशन के तौर पर खास था। शो के लिए, आलिया ने एक बोल्ड, डार्क एस्थेटिक चुना, जिसकी ऑनलाइन तुलना द मैट्रिक्स के विज़ुअल स्टाइल से की गई। उनके हालिया फैशन अपीयरेंस में सॉफ्ट कैज़ुअल लुक से ज़्यादा ड्रामैटिक रनवे-इंस्पायर्ड स्टाइलिंग में एक साफ़ बदलाव दिखा है।

# इंटीमेट सीन के दौरान बेकाबू हुआ था एक्टर

### दो दिन तक कमरे में बंद रही एक्ट्रेस

बॉलीवुड फिल्मों के इंटीमेट सीन्स अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं। अब इस मामले में एक्टर अन्नू कपूर ने खुलकर अपनी राय रखी है और एक एक्टर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। अन्नू कपूर ने दावा किया कि ऐसे कई मौके आए हैं जब इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान निर्देशक के कट कहने के बावजूद एक्टर रुका नहीं। अन्नू कपूर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कई बार देखा कि अभिनेता सीन के दौरान अपना आपा खो बैठा और सीक्वेंस को जानबूझकर लंबा खींचा गया। उन्होंने अभिनेता का नाम लिए बिना इसके बारे में खुलकर बात की।

### कट बोलने के बाद भी नहीं रुका एक्टर

सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर बोलते हुए अन्नू कपूर ने कहा,मैंने अभिनेताओं को इंटीमेट सीन्स के दौरान अपना आपा खोते हुए देखा है। निर्देशक के कट कहने पर भी वे नहीं रुकते। कई लोग ऐसी स्थितियों का फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया... एक ऐसे ही सीन के दौरान एक एक्टर बहक गया था।उन्होंने आगे कहा,कट बोलने के बावजूद एक्टर नहीं रुका। अभिनेत्री को वहां से भागने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वह इतनी सदमे में थी कि दो दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अनु कपूर की फिल्मों की बात करें तो साल 2023 में वो ड्रीम गर्ल 2 और साल 2024 में द सिग्नेचर और हमारे बारह जैसी फिल्मों में नजर आए थे। इसके अलावा वो अरशद वारसी और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 का भी हिस्सा थे।

## खेल समाचार

# बांग्लादेशी एक्सप्रेस नाहिद राणा की पीएसएल 2026 में वापसी

**बांग्लादेशी तेज गेंदबाज नाहिद राणा को बीसीबी से एनओसी मिल गई है...और वह 3 मई को पेशावर जाल्मी के लिए पीएसएल का फाइनल खेलेंगे...बोर्ड ने उनकी फिटनेस और भविष्य के विकास को देखते हुए यह फैसला लिया है...**

### फाइनल के लिए बीसीबी ने दी मंजूरी, पेशावर जाल्मी को मिला घातक गेंदबाज

**ढाका,29 अप्रैल 2026।** बांग्लादेश के उभरते हुए तेज गेंदबाज नाहिद राणा एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को नाहिद को बीसीबी जारी कर दिया है। अब वह 3 मई को होने वाले पीएसएल के ग्रैंड फिनाले में अपनी टीम पेशावर जाल्मी की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे।

### वर्कलोड मैनेजमेंट के बाद वापसी का फैसला

नाहिद राणा को शुरुआत में केवल

13 अप्रैल तक पीएसएल खेलने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण वह टूर्नामेंट से हट गए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही घरेलू टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में भी उन्हें आराम दिया गया था। हालांकि, बीसीबी ने अब माना है कि किसी बड़े वैश्विक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के फाइनल में हिस्सा लेना खिलाड़ी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बोर्ड की मेडिकल टीम और टीम प्रबंधन ने पुष्टि की है कि फाइनल में खेलने से उनकी फिटनेस या राष्ट्रीय टीम की उपलब्धता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

### जावेदी अफरीदी ने तमीम इकबाल का जताया आभार

पेशावर जाल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बुधवार को बीसीबी के नवनियुक्त अध्यक्ष तमीम इकबाल का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से नाहिद की वापसी संभव हो सकी। नाहिद की वापसी ने फाइनल से पहले पेशावर जाल्मी के गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती प्रदान की है।

### नाहिद राणा की घातक फॉर्म और आंकड़े

पीएसएल 2026 के इस सीजन में नाहिद राणा का प्रदर्शन बेमिसाल रहा है। स्वदेश लौटने से पहले उन्होंने जाल्मी के लिए खेले गए केवल 4 मैचों में 10.85 की औसत और 5.42 की इकोनॉमी रेट से 7 विकेट चटकाए थे। कराची किंग्स के खिलाफ उन्होंने महज 7 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जिसकी बदौलत कराची की टीम 87 रनों पर ढेर हो गई थी। इसके अलावा, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्होंने 8 विकेट लेकर अपनी लय साबित की थी।

# फुटबॉल स्टार क्रिश्चियन पुलिसिक और विराट कोहली ने जर्सी की अदला-बदली की

**बेंगलुरु,29 अप्रैल 2026।** यूएसए के फुटबॉल आइकन क्रिश्चियन पुलिसिक और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली, रजत पाटीदार और फिल साल्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और एसी मिलान के बीच एक क्रॉस-कॉन्टिनेंटल क्रॉसओवर में स्पोर्ट्स और जर्सी एक्सचेंज कीं। मिलान में, पुलिसिक ने नई आरसीबी जर्सी पहनकर क्रिकेट बैट उठाया और ड्राइव के लिए ड्रिबल की अदला-बदली की, जबकि भारत के कोहली, पाटीदार और साल्ट ने एक कूल फुटबॉल ट्रिक के साथ एक्सचेंज का जवाब दिया, एक ऑफिशियल रिलीज़ के अनुसार। दो शहरों और दो स्पोर्टिंग वर्ल्ड में खेले गए इस पल ने एलीट एथलीट और टीमों को एक कॉमन कॉम्पिटिटिव एज के ज़रिए जोड़ा। क्रॉसओवर पर रिएक्ट करते हुए, कोहली ने कहा,आइकॉनिक क्लब आइकॉनिक कोलाब करते हैं। सियाओ। सात बार के यूरोपियन चैंपियन एसी मिलान को मौजूदा भारतीय चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ लाने से, यह पल स्टार-स्टडेड आरसीबी जर्सी को ग्लोबल स्पोर्टिंग कल्चर के सेंटर में ले आता है। मिलान की विरासत और पुलिसिक की स्टार पावर के साथ, यह एक्सचेंज जर्सी को क्रिकेट से आगे और एलीट यूरोपियन फुटबॉल की दुनिया में ले जाता है। सही मायने में,एसी मिलान की शुरुआत एक फुटबॉल और क्रिकेट क्लब के तौर पर इसकी शुरुआत से हुई है, जिससे यह क्रॉसओवर क्लब की मल्टी-स्पोर्ट जड़ों को दिखाता है।

# क्या 2027 में पूरा हो पाएगा भारत को विश्व चैंपियन बनाने का सपना?

**नई दिल्ली,29 अप्रैल 2026।** भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक बल्लेबाज और कप्तान के रूप में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन 2023 में वनडे विश्व कप न जीत पाने का मलाल उनके दिल में अब भी जिंदा है। रोहित अपने इस अधूरे सपने को 2027 में पूरा करना चाहते हैं, और इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में एक साधारण परिवार में जन्मे रोहित शर्मा मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट के सर्वाधिक लोकप्रिय और बड़े नामों में एक हैं। 39 साल के होने जा रहे रोहित के दिल में देश के लिए खेलने और खिताब जीतने की इच्छा कम नहीं हुई है। अपनी कप्तानी में भारत को टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना चुके रोहित का आखिरी सपना दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले वनडे विश्व कप 2027 में भारत को चैंपियन बनाना है। दरअसल, रोहित ने कई बार अपने साक्षात्कारों में कहा है कि जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो उस समय सिर्फ वनडे विश्व कप होता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही देश के लिए वनडे विश्व कप जीतने का सपना देखा था। यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और इसे पूरा करने के लिए रोहित की नजर अब वनडे विश्व कप 2027 पर है।

# रिकॉर्ड तोड़ सेमी-फ़ाइनल में पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख को 5-4 से हराया

**पेरिस,29 अप्रैल 2026।** पेरिस सेंट-जर्मेन ने पीएसजी चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में बायर्न म्यूनिख को 5-4 से हराकर रोमांचक जीत हासिल की। इससे उन्हें म्यूनिख में होने वाले मैच में थोड़ी बढ़त मिल गई। बायर्न ने पहला गोल तब किया जब हैरी केन ने 17वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला। मेज़बान पीएसजी ने तेज़ी से जवाब दिया, और ख्विचा क्वारात्सखेलिया ने 24वें मिनट में शानदार कोशिश करके स्कोर बराबर कर दिया। मेज़बान टीम ने 33वें मिनट में जोआओ नेवेस की मदद से बढ़त बनाई, जिन्होंने ओस्मान डेम्बेले के कॉर्नर पर हेडर से गोल किया। हालांकि, बायर्न ने हाफटाइम से ठीक पहले स्कोर बराबर कर दिया, जब माइकल ओलिस ने 41वें मिनट में ज़बरदस्त गोल किया। पीएसजी ने हाफटाइम से ठीक पहले फिर से बढ़त बना ली जब ओस्मान डेम्बेले ने अल्फोंसो डेविस के फाउल को गलत ठहराए जाने के बाद पेनल्टी स्पॉट से गोल किया। फ्रांसीसी टीम ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही अपनी बढ़त बढ़ा ली। क्वारात्शेलिया ने 56 वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया, अचरफ हकीमी के मूव को पूरा किया। कुछ देर बाद, डेम्बेले ने काउंटर-अटैक में एक और गोल करके स्कोर 5-2 कर दिया। बायर्न ने आखिर में वापसी की, जब 65 वें मिनट में जोशुआ किमिच के फ्री किक पर डायोट उपामेकानो ने गोल किया। फिर 68 वें मिनट में लुइस डियाज़ ने स्कोर को और कम कर दिया, जब शुरुआती ऑफसाइड कॉल के बाद व्हीएआर ने उनके गोल को कन्फर्म किया।

# साय कैबिनेट की बैठक...छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मिली मंजूरी,तीन आईपीएस अधिकारियों का डिमोशन निरस्त

**रायपुर,29 अप्रैल 2026।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय,महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 'छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति,2026''को मंजूरी दी गई। वहीं तीन आईपीएस अधिकारियों का डिमोशन निरस्त किया गया। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए।

### बैठक में लिए गए ये फैसले

- ''छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026''को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा। साथ ही इस नीति से पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा,ईंधन उपयोग में विविधता आएगी और राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा,दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- मंत्रिपरिषद ने आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन,राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज भूमि में से 5 एकड़ भूमि को रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया।
- मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की जारी आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की है। यह सहायता राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने तथा विभिन्न आवश्यक परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।
- मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले, आरके विज एवं मुकेश गुप्ता के संबंध में पूर्व में जारी पदावनति आदेश दिनांक 26 सितंबर 2019 का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने दिनांक 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को अपास्त करते हुए उस निर्णय के पालन में जारी सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के उपरांत लिया गया है।

## छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में बड़े फेरबदल : रायपुर और सारंगढ़ को मिले नए चिकित्सा अधिकारी

**रायपुर,29 अप्रैल 2026।** छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के नवीन स्थानांतरण और पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत रायपुर,बिलासपुर और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के महत्वपूर्ण चिकित्सा पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में हुए इन बदलावों से जिला अस्पतालों के प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। विशेष रूप से रायपुर जिला चिकित्सालय में प्रभारी सिविल सर्जन की नियुक्ति से राजधानी की चिकित्सा व्यवस्था और बिलाईगढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नई जिम्मेदारी से स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग बेहतर हो सकेगी।

### तबादले की विस्तृत जानकारी

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार,वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. गायत्री बांधे को उनकी वर्तमान पदस्थापना से स्थानांतरित कर संभागीय संयुक्त संचालक,बिलासपुर संभाग के कार्यालय में पदस्थ किया गया है। राजधानी रायपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव हुआ है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. भेनुज कुमार सिन्हा, जो अब तक गुढ़ियरी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में सेवाएं दे रहे थे, उन्हें अब जिला चिकित्सालय रायपुर में प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र कुमार वैष्णव को पदोन्नत करते हुए प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर नियुक्त किया गया है।

## छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं रिजल्ट...लड़कियों ने फिर मारी बाजी

### जिज्ञासु ने किया टॉप,पिता की किराना दुकान,टॉपर बोली-पढ़ाई में एआई की ली मदद

**रायपुर,29 अप्रैल 2026।** छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जारी हो गए हैं। कुल 83.04% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 43 स्टूडेंट्स के नाम हैं। इसमें 33 लड़कियां हैं। बलौदाबाजार जिले के पलारी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है। जिज्ञासु ने 98.60 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। वहीं बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल की छात्रा ओमनी वर्मा ने 98.20% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिले के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल छाल के छात्र कृष महंत रहे, जिन्होंने 97.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। साय सरकार ने टॉपर्स को 1.5 लाख देने का ऐलान किया है। 12वीं परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 86.04 प्रतिशत रिजल्ट हासिल किया, जबकि लड़कों का परिणाम 78.86 प्रतिशत रहा। करीब 2.44 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से लगभग 2.02 लाख छात्र-छात्राएं पास हुए।

### सालेहा पारेख को 95% अंक मिले

कोंडागांव के केशकाल पीएम श्री आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्रा सालेहा पारेख ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक अर्जित कर जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है।

### बुनकर परिवार के बेटे ने हासिल किया 9वां स्थान

बलौदाबाजार जिले के छोटे से गांव कटगी के नितेश देवांगन ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की प्रदेश मेरिट सूची में 9वां स्थान हासिल किया है। कपड़े बुनने वाले साधारण परिवार से आने वाले नितेश की इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। जैसे ही मेरिट सूची में उनका नाम आने की खबर मिली,परिवार की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। रायपुर श्रीनगर डेजल पब्लिक स्कूल की छात्रा आफिया खातून ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में प्रदेश की मेरिट सूची में 9वां स्थान हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है। आफिया के पिता मोहम्मद अनवर मोटर मैकेनिक हैं।

### गरियाबंद जिले से 12वीं मेरिट लिस्ट में 4 छात्राएं

गरियाबंद जिले की बेटियों ने इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षा में नया इतिहास रच दिया है। पहली बार जिले से 12वीं की मेरिट सूची में चार विद्यार्थियों ने जगह बनाई हैं। छुरा की महक सचदेवा ने 97 प्रतिशत अंक के साथ 7वां स्थान हासिल किया,जबकि कौंदकेरा की तनीशा ने 96.80 प्रतिशत के साथ 8वीं रैंक प्राप्त की। वहीं रावणसिंघी की विद्यारानी और राजिम की प्रेमीन सोनकर ने 96.40 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप-10 मेरिट सूची में जगह बनाई। 10वीं बोर्ड में भी जिले की बेटी दीपांशी बौद्ध ने दूसरा स्थान हासिल किया है। डीईओ जगजीत सिंह धीर ने टॉपर छात्राओं के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और कहा कि बेटियों ने जिले को नई पहचान दिलाई है।

### छत्तीसगढ़ 10वी बोर्ड रिजल्ट

#### टॉप 10 में 26 लड़कियां... महासमुंद की संध्या-परीरानी,मुंगेली के अंशुल शर्मा को 99% मिल

छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टॉप 3 में महासमुंद जिले की 2 लड़कियों ने 99% के साथ टॉप किया है। इनमें एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा की संध्या नायक और एकलव्य स्कूल बलौदा की परीरानी प्रधान शामिल है। तीसरे नंबर पर मुंगेली के अंशुल शर्मा है, इन्होंने भी 99% लाया है। संध्या किसान परिवार से आती है,रिजल्ट जारी होने के बाद उन्होंने भविष्य में डिप्टी कलेक्टर बनने की बात कही। अंशुल के पिता इंश्योरेंस एडवाइजर, उन्होंने 11वीं में मैथ्स लेकर JE की तैयारी करने की बात कही। परीरानी प्रधान ने डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने की इच्छा जताई। बता दें कि इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 3 लाख 21 हजार स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था,इनमें 77.15% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 42 स्टूडेंट्स मेरिट में आए हैं, इनमें 26 लड़कियां शामिल हैं। राज्य सरकार ने टॉपर्स को डेढ़ लाख देने का ऐलान किया है।

### टॉपर बोली...रटने से ज्यादा समझने पर फोकस किया

रिया केशरवानी ने बताया कि वो रटने से ज्यादा समझने पर फोकस करती थी। रेगुलर पढ़ाई करती थी। उन्होंने कहा कि हमारे गवर्मेंट स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं। मम्मी पापा ने भी पूरा सपोर्ट किया। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं,इसके लिए बायो सबजेक्ट लेकर आगे की पढ़ाई करुंगी।

### बिलासपुर की नैनसी ठाकुर के 97.05%

बिलासपुर चकरभाटा स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्रा नैनसी ठाकुर ने टॉप 10 में जगह बनाई है। उन्होंने 97.05 अंक हासिल किया है,नैनसी अब गणित विषय लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहती हैं।

### रायपुर की दीपांशी बौद्ध को 98.83%

दीपांशी बौद्ध 98.83% के साथ सेकेंड पॉजीशन पर है। वह गरियाबंद जिले के सड़कपरसूली की रहने वाली है। रायपुर गुढ़ियारी स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। परीरानी प्रधान बलौदा के एकलव्य स्कूल की छात्रा है, उन्होंने 99% परसेंट के साथ टॉप किया है। महासमुंद जिले के बलौदा गांव की परीरानी प्रधान ने 99% के साल पूरे प्रदेश में टॉप किया है। परीरानी ने बताया कि वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। उनके पिता सुशील प्रधान ट्रैक्टर पार्ट्स का दुकान चलाते हैं।

## दुर्ग ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी को मौत की सजा

### पत्नी-बेटी को जिंदा जलाया,खुद को मरा साबित करने मानसिक रोगी का गला घोंटा

**दुर्ग-भिलाई,29 अप्रैल 2026।** छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में दुर्ग कोर्ट ने 6 साल बाद आरोपी रवि शर्मा को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 का है,जिसमें आरोपी ने अपनी पत्नी और डेढ़ साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी थी। उस पर किसी को शक न हो इसके लिए उसने एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी मार दिया,ताकि वो खुद को मरा हुआ साबित कर सके। जांच में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी और बच्चे राउरकेला में रहते हैं। भिलाई में उसने मंजू से दूसरी शादी कर ली थी। मंजू ने डेढ़ महीने पहले बच्ची को जन्म दिया था,लेकिन रवि इस बच्चे को नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। आखिरकार

तंग आकर उसने मंजू को मारने की योजना बना ली। पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर पता लगा लिया था कि तीनों मर्डर के पीछे रवि शर्मा का ही हाथ था। जांच के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल्स, इस्तेमाल किए गए सामान और दवाइयों की जांच, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जैसे अहम सबूत सामने आए। इन सभी सबूतों के आधार पर दुर्ग कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आरोपी को हत्याकांड के लिए मौत की सजा सुनाई। इस मामले में दुर्ग न्यायालय में शासकीय वकील भावेश कटरे ने पैरवी की। भिलाई नगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश कुमार ध्रुव ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। घटना 21 जनवरी 2020 की सुबह की है। भिलाई के तालपुरी स्थित पारिजात कॉलोनी में रहने वाली मंजू शर्मा के मोबाइल से सुबह करीब 5:35 बजे उसकी मां कला सूर्यवंशी को फोन आया। फोन पर किसी ने कहा कि तुम्हारी बेटी और दामाद घर में जल रहे हैं, बचा सको तो बचा लो। इसके बाद फोन कट गया। परिवार के लोग जब मौके पर पहुंचे तो घर बाहर से बंद था,लेकिन अंदर से धुआं निकल रहा था। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो नजारा देखकर सब दंग रह गए। कमरे में मंजू शर्मा की अधजली लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसके हाथ-पैर और मुंह टेप से बंधे हुए थे। पास में डेढ़ माह की बच्ची भी मृत अवस्था में मिली। वहीं बिस्तर के नीचे एक और युवक का शव पड़ा था, जिसका चेहरा भी टेप से ढंका हुआ था और शरीर का हिस्सा जला हुआ था। पहले ऐसा लगा कि तीसरा शव रवि शर्मा का है, लेकिन जांच में पता चला कि वह कोई अज्ञात व्यक्ति है। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि मामला कुछ और है।

**जांच में सामने आई साजिश :** घटनास्थल पर बेडरूम के दरवाजे पर चाक से लिखा मिला कि मंजू बेवफा थी, इसलिए मजबूरी में उसे, उसके पति और बच्चे को मारना पड़ा। नीचे संजय देवांगन आर्मी लिखा था। यह लिखावट भी पुलिस को भटकाने के लिए थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि घटना से एक दिन पहले रवि एक अज्ञात युवक को स्कूटी से अपने घर लेकर आया था।

## छत्तीसगढ़ बोर्ड पेपर लीक केस... फरार-आरोपी पर 5 हजार का इनाम

### गिरफ्तारी की मांग लेकर एनएसयूआई कमिश्नर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

**रायपुर,29 अप्रैल 2026।** छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी वेणुगोपाल वेणु पर रायपुर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। सिटी कोतवाली थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 130/2026 में आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही है,लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब पुलिस ने आरोपी की सूचना देने या गिरफ्तारी कराने वाले को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं,पेपर लीक मामले को लेकर छात्र राजनीति गरमा गई है। मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में NSUI कार्यकर्ता को कमिश्नर कार्यालय, सिविल लाइन पहुंचकर प्रदर्शन किया। NSUI का कहना है कि पेपर लीक जैसी गंभीर घटना के बाद भी अब तक मुख्य आरोपी

पर कार्रवाई नहीं होना लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने पुलिस जांच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं बड़े मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश हो रही है।

**वेणु जंघेल पर 5 हजार रुपए का इनाम :** पुलिस के मुताबिक आरोपी वेणु जंघेल (18) बेमेतरा जिले के बोरतरा गांव का निवासी है। वह वर्तमान में रायपुर के अशोक नगर गुढ़ियारी में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ परीक्षा अधिनियम की धारा 4,5,10 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत मामला दर्ज है। यह मामला 14 मार्च 2026 को सामने आए परीक्षा अनियमितता और पेपर लीक केस से जुड़ा है। सेंट्रल जोन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर डॉ. अर्चना झा ने रायपुर पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए के तहत इनाम घोषित करने का आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा हुआ है और उसके खुलेआम घूमने से समाज के लिए खतरा हो सकता है।

## जनगणना ड्यूटी पर लगे अधिकारी-कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर

**रायपुर,29 अप्रैल 2026।** छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशभर में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक रहेगी। ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो जनगणना 2027 के काम में लगे हुए हैं। दरअसल,मोदी सरकार ने साल 2027 में देशभर में जनगणना करवाने का फैसला लिया है। ये भारत की 16 वीं जनगणना होगी,जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है। वहीं, 1 से 30 मई तक सर्वेयर घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में राज्य सरकार ने जनगणना 2027 ड्यूटी पर लगे अधिकारी/ कर्म चारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह भी कहा कि अगर कोई बेहद खास या जरूरी हो तभी ट्रांसफर पर विचार किया जा सकता है।

## छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस संतोष सिंह सीआईएसएफ में बने डीआईजी

**रायपुर,29 अप्रैल 2026।** छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह ने हैदराबाद स्थित मुख्यालय में सीआईएसएफ साउथ जोन-2 के डीआईजी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इस पद के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक की सीआईएसएफ-संरक्षित इकाइयों जैसे खदान, कारखाने,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा भी इनके अधीन होगी। इससे पहले आईपीएस संतोष सिंह छत्तीसगढ़ के कई चुनौतीपूर्ण जिलों में कप्तानी कर चुके हैं। विशेष रूप से रायपुर एसएसपी के रूप में उनके कार्यकाल को काफी सराहा गया था। वर्तमान में वे पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।

### 'निजात' अभियान से बनाई देशभर में पहचान

आईपीएस संतोष सिंह केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही नहीं,बल्कि अपने नवाचारों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने नशामुक्ति के लिए शुरू किए गए 'निजात' अभियान की तारीफ केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। कोरिया,राजनांदगांव और कोरबा जैसे जिलों में एसपी रहते हुए उन्होंने अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)